RNI NO. CHHHIN/2022/83778

न्यूज रूटीन

मासिक, बलौदाबाजार से प्रकाशित

बढ़ते हुए कदम

जब अकेले होते हैं तो आध्यात्मिक बन जाते हैं और जब समूह में होते हैं तो धार्मिक बन जाते हैं

वर्ष : 03 | अंक : 10 | मासिक, बलौदाबाजार, अक्टूबर 2024 | E-mail: newsroutine6@gmail.com | पृष्ठ : 08 | मूल्य : 15 रू.

साय सरकार का बड़ा फैसला, 14 नवंबर से होगी धान खरीदी, दिवंगत शिक्षक पंचायत के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 14 नवंबर से धान खरीदी का फैसला लिया गया. इसके साथ दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का भी फैसला लिया गया.

मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया. मंत्रिमण्डलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवम्बर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया. राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी.

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी. वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी.

मंत्रिपरिषद में खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन के लिए सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदाय करने का निर्णय लिया गया. सभी खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से धान खरीदी होगी. धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नये जूट बारदाना जूट कमिश्नर के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति दी गई है. धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी.

मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपए प्रतिमाह के मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया. इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपए का व्यय भार आएगा. जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षों की भांति राशि मार्कफेड को प्रदाय की जाएगी.

विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित 49 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है.

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ-साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी देखेगी. ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण के अलावा नये कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण एवं शिकायतों का निराकरण करेगी.

दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इसके तहत ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी, और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा हेतु पात्र है, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी. ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सके.

मीसाबंदियों का राजकीय सम्मान के साथ होगी अंत्येष्ठि,अंतिम संस्कार के लिए दी जाएगी 25 हजार की सहायता

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि की जाएगी तथा अंत्येष्ठि के लिए उनके परिवार को 25 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी.

देशी/विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किये जाने हेतु Excise Adhesive Label (Hologram) होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाइयों एवं कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया.

रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा

13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे होंगे घोषित

रायपुर। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. यहां 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होगी.

चुनाव आयोग के मुताबिक, नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर होगी. 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी. वहीं नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है. बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा से टिकट दी गई थी. रायपुर से उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. उनकी जीत के बाद रायपुर दक्षिण एक मात्र ऐसी सीट है, जहां उपचुनाव होंगे.

सामान्य सीट इसलिए दावेदार अधिक

दक्षिण विधानसभा की सीट सामान्य वर्ग की श्रेणी में आती है. यानी इस सीट के लिए किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है. यही वजह है कि यहां दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इस उपचुनाव में कांग्रेस-भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी. यह सीट लंबे समय से भाजपा के कब्जे में है. ऐसे में भाजपा के सामने अपनी परंपरागत सीट को बचाए रखने की चुनौती होगी. वहीं कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि इस बार दक्षिण में अपनी जीत हासिल करे.

भाजपा का गढ़ है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट

रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है. यहां से भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल 1990 से 2023 तक लगातार आठ विधानसभा चुनाव जीते हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी. उन्होंने कांग्रेस के महंत रामसुंदर दास को 60 हजार से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हराया था. 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल को एक लाख नौ हजार दो सौ तीरसठ वोट और कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास को 41 हजार 544 वोट मिले थे. बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बृजमोहन को रायपुर से प्रत्याशी बनाया था, जहां जीत हासिल करने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था.

कांग्रेस ने बनाई है 9 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति

छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. उपचुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए कांग्रेस ने 9 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है. यह समिति पूरी चुनावी तैयारियों पर नजर रखेगी. कांग्रेस की उपचुनाव समिति में 6 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायक समेत सीनियर नेताओं को जवाबदारी दी गई है, जिसमें पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, रविन्द्र चौबे, मोहन मरकाम, शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, रुचिर गर्ग और उधो राम वर्मा शामिल हैं.

बिना विभागीय अनुमति के अब राजस्व अधिकारियों पर नहीं होगी एफआईआर

रायपुर। राजस्व अधिकारियों की मन की मुराद पूरी हो गई है. अब बिना विभागीय अनुमति के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी. छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ इस संबंध में लंबे समय से मांग करता रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने तमाम संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 और न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के तहत राजस्व अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त होने की बात कही है.

राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण उपरांत असंतुष्ट पक्षकारों द्वारा विधिवत अपील की कार्यवाही न कर सीधे पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा रही है, और पुलिस भी प्राथमिकी दर्ज कर पीठासीन अधिकारी को नोटिस दे रही है. इस प्रकार न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त नहीं हो पा रहा है.

इसके साथ असंतुष्ट पक्षकारों के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध सीधे सिविल न्यायालय में वाद दायर कर दिया जा रहा है, और सिविल न्यायाधीश स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में पुलिस को प्राप्त शिकायत की जांच के लिए भेज रहे हैं, और पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.

सचिव ने अधिनियमों का हवाला देते हुए बताया कि न्यायायिक अधिकारियों की सद्भावना में किए गए न्यायालय के कार्य अथवा पारित आदेशों के विरूद्ध सिविल न्यायालय में मुकदमा चलाए जाने के संबंध में संरक्षण प्राप्त है. इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय के रूप में काम करता है, उसे उपरोक्तानुसार संरक्षण प्राप्त है. इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया संरक्षण इसी सिद्धांत पर दिया गया है कि जो व्यक्ति न्यायालय के रूप में कार्य करता है उसके कर्तव्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह व्यक्ति बिना किसी भय के कार्य कर सके.

संघ ने सचिव का जताया आभार

कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने कहा कि हम विभागीय सचिव अविनाश चंपावत का आभार अभाव व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा है. हमने इस मांग को पिछले दिनों प्रमुखता से उठाया था.

बस्तर दशहरा हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक

मांझी-चालकी और मेम्बर-मेंबरीन के मानदेय में बढ़ोतरी हेतु प्रशासन और बस्तर दशहरा समिति से प्रस्ताव प्रस्तुत करने दिए निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व हमारी आस्था और परम्परा का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो सर्वाधिक लम्बी अवधि तक मनाया जाता है। बस्तर दशहरा पर्व को बस्तर अंचल के सभी लोग पूरी श्रद्धा-आस्था के साथ मनाते हैं और इसमें सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। वहीं ऐतिहासिक बस्तर दशहरा अब देश-दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो गया है, जिससे अब पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ ही स्थानीय लोगों की आय को संबल मिला है। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से बस्तरवासियों की अगाध श्रद्धा और सभी लोगों के सहयोग से इस वर्ष भी बस्तर दशहरा का भव्य एवं सफल आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उक्ताशय के उद्गार आज जगदलपुर के सिरहासार भवन में विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के अवसर पर आयोजित मुरिया दरबार को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने इस अवसर पर माडिया सराय में विकास कार्य के लिए 50 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मांझी-चालकी और मेम्बर-मेंबरीन के मानदेय में बढ़ोतरी हेतु जिला प्रशासन और बस्तर दशहरा समिति से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर दशहरा पर्व के ऐतिहासिक मुरिया दरबार में सम्मिलित होने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि मुरिया दरबार का आयोजन सदियों से होता आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर दशहरा पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है जिसे हम सभी एकजुट होकर श्रद्धा और सहकार की भावना के साथ हर्षोल्लास मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से विकसित दशराहा पसरा को बस्तर दशहरा पर्व में आए मांझी-चालकी तथा अन्य लोगों को सुविधा मुहैया करवाने की दिशा में सार्थक प्रयास बताया और कहा कि बस्तर दशहरा पर्व के लिए निर्धारित बजट को 50 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने मुरिया दरबार में मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन और बस्तर दशहरा समिति के पदाधिकारियों की मांग एवं समस्याओं को निराकृत किए जाने की बात कही।

मुख्यमंत्री साय एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का किया मुआयना

- मुख्यमंत्री ने महिला समूहों के प्रयास को सराहा
- प्लास्टिक कचरे की रिसाइकिल से पर्यावरण प्रदूषण में आएगी कमी
- राजनांदगांव जिले के अमलीडीह में संचालित है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट

राजनांदगांव। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने आज राजनांदगांव जिले के अमलीडीह गांव के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में महिला समूहों द्वारा संचालित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का मुआयना किया। उन्होंने प्लास्टिक कचरे की रिसाइक्लिंग करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे महिला समूहों के प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गांधी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला समूह से चर्चा करते हुए कहा कि आप सबका यह प्रयास राज्य और देश में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से हम प्लास्टिक कचरा को रिसाइकलिंग कर पर्यावरण को रहे नुकसान को कम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि महिला समूह ने अपने विशेष प्रयासों से रोजगार और स्वावलंबन हासिल करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम किया है।

इस अवसर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि महिलाएं आज अनेक क्षेत्रों में अपने हुनर व मेहनत से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं। महिला समूह आत्मसम्मान के साथ रोजगार और स्वावलंबन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट से मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषित होती है। इससे जीव-जंतु का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिला समूह ने जो प्लास्टिक कचरा को रिसाइक्लिंग करने का बीड़ा उठाया है, यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कारगर साबित होगा।

गरीबों को 2028 तक मुफ्त में मिलता रहेगा फोर्टिफाइड चावल

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल की मुफ्त आपूर्ति खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 17,082 करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2028 तक जारी रखने का बुधवार को फैसला किया। पौष्टिक तत्वों से भरपूर यानी फोर्टिफाइड चावल लोगों में खून की कमी (एनीमिया) के समाधान और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए अहम माना जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चावल को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने की प्रक्रिया में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों (लौह, फोलिक एसिड, विटामिन बी12) से भरपूर 'फोर्टिफाइड' चावल कर्नेल (एफआरके) को नियमित चावल (कस्टम मिल्ड चावल) में मिलाया जाता है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए कुल वित्तीय योजना 17,082 करोड़ रुपये की होगी। इस व्यय का पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार करेगी।

बयान के अनुसार, चावल को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने की पहल केंद्रीय क्षेत्र की पहल के रूप में जारी रहेगी। इसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण पीएमजीकेएवाई (खाद्य सब्सिडी) के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत संस्थागत तंत्र उपलब्ध होगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में पोषण सुरक्षा की जरूरत बताई थी। सरकार ने कहा है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), अन्य कल्याणकारी योजनाओं, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), पीएम पोषण (पूर्ववर्ती एमडीएम) के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की पहल की गई है।

एसडीएम व तहसील कार्यालय में अनुपस्थित 5 कर्मचारियों को नोटिस

संभागायुक्त महादेव कावरे ने किया कार्यालयों का निरीक्षण

बिलासपुर। बिल्हा के शासकीय कार्यालयों में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने संभागायुक्त महादेव कावरे अचानक गुरुवार को पहुंचे। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान एसडीएम व तहसील कार्यालय में 5 कर्मचारी गायब थे, जिन्हें संभागायुक्त ने तत्काल नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने लंबित भू-अर्जन मुआवजा राशि के 4.5 करोड़ रुपये का वितरण शीघ्र करने और राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया है।

समय पर नहीं पहुंचे, तो होगी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान बिल्हा तहसील कार्यालय पहुंचे पर संभागायुक्त महादेव कावरे ने पाया कि सुशील कुमार दुबे, एम कश्यप, जगन्नाथ व दिलीप वस्त्रकार अपनी जगह पर नहीं है। किसी को इनके आने या कही काम से जाने की जानकारी नहीं थी। इसी तरह एसडीएम कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कालिंदी देवांगन अनुपस्थित थी। संभागायुक्त ने कहा कि कार्यालय में समय पर उपस्थित रहना और जनता के कार्यों का निपटान तेजी से करना अनिवार्य है।

कार्यालयों में अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर

संभागायुक्त महादेव कावरे ने निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारियों को अपनी पहचान के लिए नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया इससे आमजन के साथ संवाद और सेवाएं दोनों में सुगमता आएगी। फाइलों को व्यवस्थित रखने और जनता के साथ सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने के भी निर्देश दिए।

लंबित मुआवजे का शीघ्र वितरण

संभागायुक्त ने भू-अर्जन से संबंधित लंबित 4.5 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि का शीघ्र वितरण करने को कहा। उनका कहना था कि किसानों को जल्द मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी समस्याओं से उबर सकें। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना था, जिससे जनता को सेवाएं समय पर और प्रभावी ढंग से मिल सकें।

अतिक्रमित सैकड़ों एकड़ वन भूमि से 42 परिवारों को हटाया गया

मुंगेली। जिले मुंगेली वनमंडल के खुड़िया वन परिक्षेत्र के कंसरी बीट में वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई किया। मुंगेली वनमण्डल के खुड़िया वन परिक्षेत्र के कंसरी बीट में वन विभाग,पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई किया।

इस कार्रवाई में करीब 42 परिवार अवैध रूप से बेजा कब्जा किए भूमि को खाली कराया जा रहा। मौके पर लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी, एसडीओपी माधुरी धिरही,वन विभाग के एसडीओ प्रशांत दशहंस सूर्यवंशी सहित अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात रहें।

अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण यहां की वन संपदा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था,जिसके चलते यह कदम उठाया गया है।

लंबे समय से अतिक्रमणकारी हरे - भरे पेड़ों को काटकर खेत बना रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से कई बार शिकायतें करने के बाद,अब विभाग ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है। सुबह से जेसीबी मशीनों के माध्यम से दर्जनों कच्चे मकानों को ध्वस्त करने का काम किए गए। यह कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है, जिसमें विभाग ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर्ताओं को चिन्हित कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। इस संयुक्त कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है और वन विभाग की तत्परता की सराहना किया जा रहा है।

निजी प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों को नोटिस

रायगढ़। जिले के लखीराम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने पर बड़ी चेतावनी जारी की गई है. मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने अस्पताल के साथ-साथ अपने अधीनस्थ सभी 100 से अधिक विभागाध्यक्षों और डॉक्टरों को नोटिस भेजा है, जिसमें सरकारी कार्यों के दौरान नियमों के उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों में मरीजों की परेशानी को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के बाद भी लगातार निजी प्रैक्टिस में लिप्त डाक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है. शासन के नए आदेशानुसार मेडिकल कालेज में पदस्थ डॉक्टरों को अब अस्पताल के समय में ड्यूटी पर उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है और इस तय अवधि में वे मरीजों के इलाज में अपनी सेवाएं देते रहें. अगर इस दौरान अगर किसी निजी चिकित्सालय या निजी क्लीनिक पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए जाने पर ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि नियमानुसार अन्य कड़े कदम उठाये जा सकते हैं.

इस संबंध में स्व. लखीराम मेडिकल कालेज के डीन डॉ. पीएम लुका ने बताया कि हाल ही में मिली शिकायत के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष सहित मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है और इस नोटिस में यह कहा गया है कि शासकीय कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही डॉक्टर न करें. साथ-साथ मेडिकल कॉलेज में तय समय पर अगर वे अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे.

बिलाईगढ़ में किया गया स्वच्छता थीम पर विभिन्न प्रतियोगिता

बिलाईगढ़। देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत नगर पंचायत बिलाईगढ़ में भी नगर पंचायत अध्यक्ष रामनारायण देवांगन एवं पार्षदों के सुझाव तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील चौधरी के मार्गदर्शन पर स्वच्छता थीम पर विभिन्न प्रतियोगिता बिलाईगढ़ में किया गया। नगर के सभी शालाओं के छात्र - छात्राओं के लिए इंटर स्कूल विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया।

जिसमें कविता लेखन,निबंध लेखन,चित्रकला,पोस्टर निर्माण, क्विज कंपीटिशन ,स्वच्छता दौड़, सायकल मैराथन,रंगोली,वेस्ट टू आर्ट,स्लोगन,स्वच्छता शपथ, मानव श्रृंखला निर्माण एवं स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। ये सभी प्रतियोगिताएं प्रथमतः विद्यालय स्तर पर अलग - अलग आयोजित की गई। इसके पश्चात इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन नगर पंचायत बिलाईगढ़ के प्रांगण में गांधी और शास्त्री जयंती पर एक साथ किया गया। इन प्रतियोगिताओं में नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र - छात्राओं ने सहभागिता निभाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र - छात्राओं का चयन निर्णायक दलों द्वारा किया गया तथा चयनित छात्र - छात्राओं को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कड़ी में अन्य विद्यालयों के साथ नगर पंचायत बिलाईगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के छात्र - छात्राओं ने भी बढ़ - चढ़ कर हिस्सा लिया तथा अनेक प्रतियोगिताओं में प्रथम,द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। सेजेस बिलाईगढ़ की मेघा यादव कक्षा 11 वीं चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम,ऐंजल कोसले कक्षा 8 वीं पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता में प्रथम,कनिका यादव कक्षा 11 वीं स्लोगन लेखन में प्रथम एवं दीप्ति साहू कक्षा 12 वीं कविता लेखन में प्रथम स्थान प्राप्त कर गौरवान्वित हुआ। ओवरऑल स्वच्छता रैंकिंग के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी,हिन्दी माध्यम विद्यालय बिलाईगढ़ को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया।

छ.ग.राज्य महिला आयोग में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति

लक्ष्मी वर्मा,सरला कोसरिया, ओजस्वी मांडवी,दीपिका सोरी, प्रियंवदा सिंह जूदेव शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में भागीदारी को लेकर अब भाजपा नेताओं का इंतजार खत्म हो चुका है। धीरे - धीरे नियुक्तियां आदेश जारी हो रहे है, इस कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में 05 भाजपा नेत्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा (बलौदाबाजार), सरला कोसरिया (महासमुंद), स्व.भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी (दंतेवाड़ा), दीपिका सोरी (सुकमा) और प्रियंवदा सिंह जूदेव (जशपुर) को सदस्य बनाया गया है। वैसे नियुक्ति आदेश में तिथि 26 सितंबर का उल्लेख है,लेकिन सार्वजनिक गुरुवार 03 अक्टूबर को किया गया। इसकी मुख्य वजह पितृपक्ष रहा,जिसमें नियुक्ति आदेश जारी करने से बचा गया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर अभी डॉ.किरणमयी नायक काबिज है। उल्लेखनीय हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में 05 सदस्यों की नियुक्ति से यह माना जा रहा हैं कि आने वाले समय में लक्ष्मी वर्मा को - आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उक्त आदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।

महिला आयोग में नियुक्त सदस्यों ने किया पदभार ग्रहण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के आधी आबादी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए गठित राज्य महिला आयोग में महिला सदस्यों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 26 सितम्बर 2024 को की गई। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के रिक्त 05 पद पर सदस्यों की नियुक्ति की गई। बलौदाबाजार की श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने 7 अक्टूबर को ही आयोग कार्यालय आकर पदभार ग्रहण कर ली थी। महिला आयोग कार्यालय में सदस्यगण जशपुर की श्रीमती प्रियंवदा सिंह जूदेव, महासमुन्द की श्रीमती सरला कोसरिया, दंतेवाड़ा की श्रीमती ओजस्वी मंडावी और सुकमा की दीपिका सोरी ने आज आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं के हितों में मिलकर कार्य करने के लिए कहा।

कलेक्टर धर्मेश साहू ने शासकीय कन्या हाईस्कूल बरमकेला का निरीक्षण किया

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरमकेला का विगत दिवस आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें स्कूल के कक्षाओं में पहुंचकर- छात्राओं एवं शिक्षकों से रूबरू हुए एवं कैरियर मार्गदर्शन, अध्ययन- अध्यापन, विषय की कठिनाइयां के संबंध में जानकारी ली साथ ही छात्राओं को जानकारी ली कि किसको, किसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा, तब 4 छात्राओं ने नहीं मिलने की बात कहीं। कलेक्टर ने कक्षा शिक्षक एवं प्राचार्य को उनकी छात्रवृत्ति में आ रही कठिनाइयों को तत्काल समाधान करने निर्देशित किया। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रयोगशाला व्यवस्थित नहीं पाया गया। शिक्षकों के डेली डायरी, नियमित लेखन एवं उच्च कार्यालय के निर्देशन के पालन सुनिश्चित, कमजोर छात्राओं को विशेष ध्यान देकर दक्ष करने में सहयोग के लिए कलेक्टर ने शिक्षकों को कहा।

कलेक्टर धर्मेश साहू ने बोर्ड परीक्षा हेतु आवश्यक तैयारी, छात्राओं को मार्गदर्शन करने ,विद्यालय के विभिन्न अभिलेखों का नियमित संधारण, शिक्षकों की उपस्थिति संधारण संकुल स्तर पर सुनिश्चित करें, परीक्षा पंजी का अलग फोल्डर बनाकर संधारण,सभी विषयों का पुनः अभ्यास कराने, छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए निर्देशित किया, वहीं अनुपस्थित शिक्षकों की ऑनलाइन छुट्टी नहीं लेने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राचार्य इन सभी बातों को ध्यान में रखकर शिक्षकों से शिक्षकीय कार्य कराने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम प्रखर चंद्राकर, परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान ,जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी.पटेल, प्रज्ञा यादव सीईओ जनपद पंचायत, कमल कवंर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नरेंद्र कुमार जांगड़े बीईओ, अवधेश पाणिग्राही खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी किशोर कुमार पटेल, बीआरसीसी राजकमल नायक, महावीर प्रसाद नायक आदि उपस्थित थे।

उप पंजीयक कार्यालय भटगांव का शुभारंभ

भटगांव। जिला सारंगढ़ - बिलाईगढ़ के नगर पंचायत भटगांव में नवनिर्मित तहसील कार्यालय एवं उप पंजीयक कार्यालय का जांजगीर चाम्पा सांसद कमलेश जांगड़े एवं बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे ने फीता काट कर किया उद्घाटन। लोकार्पण कार्यक्रम में छाया विधायक डॉ. दिनेश लाल जांगड़े,सुभाष जलान जिलाध्यक्ष भाजपा,डॉ.हेमचंद्र जांगड़े पूर्व सदस्य छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग रायपुर,वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधिवक्ता रामनारायण भट्ट,नेमीचंद केशरवानी,दीपक कुमार टंडन अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिलाईगढ़ सहित समस्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधी,कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता,अधिकारी कर्मचारी गण बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के देव तुल्य जनता अधिक संख्या में उपस्थित रहे।

राजनांदगांव जिले के तीन राईस मिलर्स पर कार्रवाई

6800 क्विंटल धान एवं 2750 क्विंटल चावल जब्त

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में कस्टम मिलिंग का शेष चावल जमा कराने को लेकर राजनांदगांव जिले में प्रशासन द्वारा राईस मिलर्स के विरूद्ध जांच-पड़ताल और कार्रवाई का अभियान शुरू कर दिया गया है। कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने में उदासीनता बरतने वाले तीन राईस मिलों के संचालकों को नोटिस जारी करने के साथ ही उनकी राईस मिलों में स्टॉक की गड़बड़ी का मामला पकड़ में आने पर 6800 क्विंटल धान और 2750 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम राईस मिलों में औचक दबिश देकर धान एवं चावल के स्टॉक का मिलान सहित अन्य दस्तावेजों की लगातार जांच-पड़ताल कर रही है।

खाद्य अधिकारी श्री रविन्द्र सोनी ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम ने मां परमेश्वरी राईस मिल चारभाठा डोंगरगढ़, श्री श्याम इंडस्ट्रीज महराजपुर छुरिया और मेसर्स एमजे फूड प्रोडक्ट डोंगरगढ़ में निरीक्षण के दौरान धान और चावल के स्टॉक में कमी पाए जाने के चलते उक्त तीनों मिलों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की है। माँ परमेश्वरी राईस मिल चारभाठा डोंगरगढ़ से 800 क्विंटल धान एवं 1000 क्विंटल चावल, श्री श्याम इंडस्ट्रीज महराजपुर छुरिया से 500 क्विंटल धान एवं 1450 क्विंटल चावल तथा मेसर्स एमजे फूड प्रोडक्ट डोंगरगढ़ से 4000 क्विंटल धान एवं 1800 क्विंटल चावल जब्त किया है।

गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को प्रदाय किए गए धान के एवज में 31 अक्टूबर तक शत-प्रतिशत मात्रा का चावल जमा किया जाना है। राजनांदगांव जिले में एफसीआई में 99842 मिट्रिक टन चावल तथा नागरिक आपूर्ति निगम में 16067 मिट्रिक टन अरवा चावल जमा किया जाना शेष है। शेष चावल की मात्रा एफसीआई एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराने के निर्देश राईस मिलरों को दिए गए हैं।

कलेक्टर ने की महिला बाल विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा

मोहला। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना एवं सेक्टर वार आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि सतत रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें। हर एक बच्चा को लक्ष्य में रखकर बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर का मूल्यांकन करने कहा है। कुपोषित बच्चों को सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण युक्त आहार का वितरण करें। बच्चों के वजन एवं उसकी ऊंचाई की नाप हर माह करें। बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप में डाटा एंट्री का कार्य को प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, इससे कलेक्टर ने अप्रसन्नता जाहिर करते हुए संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता पर नियमानुसार डाटा एंट्री कार्य को प्राथमिकता देने निर्देशित करने कहा है। डाटा एंट्री कार्य में प्राथमिकता नहीं दिए जाने की स्थिति में संबंधित कार्यकर्ता पर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने बैठक में महिला बाल विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि गर्भवती माता, किशोरी बालिका एवं बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करें। आंगनबाड़ी केंद्र के सभी बच्चों का आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

जनसंपर्क विभाग के सचिव पी. दयानंद ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण - पी. दयानंद

रायपुर। जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। पिछले 10 माह में राज्य सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए अनेक फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से

शासन की योजनाओं का बेहतर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। वे आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद भवन में विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

सचिव श्री पी दयानंद ने कहा कि लोगों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर सूचना क्रांति का है ऐसे में सोशल मीडिया का महत्व बढ़ते जा रहा है। जनसंपर्क अधिकरियों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समाचार माध्यमों को त्वरित रूप से समाचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव श्री पी दयानंद ने कहा कि समाचार की भाषा शैली सरल, आकर्षक और पठनीय होनी चाहिए। सफलता की कहानी में किसी व्यक्ति के जीवन आए बदलाव के बारे में तथ्यपरक जानकारी और सुसंगत फोटोग्राफ का उपयोग किया जाए। राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं और नवाचारी कार्यों के संबंध में समय-समय पर विशेष लेख नियमित रूप से जारी किया जाए।

उन्होंने कहा कि नगरीय योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स नगरीय क्षेत्रों में लगाए जाएं और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं की होर्डिंग्स तहसील मुख्यालयों और जनपद पंचायतों के परिसर में लगाए जाएं। उन्होंने बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडया और क्षेत्रीय स्तर पर प्रिंट मीडिया में प्रचार-प्रसार कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए।

उन्होंने बैठक में जिला जनसंपर्क कार्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे शासन के कार्यों और फ्लैगशिप योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विभागीय सेट-अप की भी जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। सचिव श्री दयानंद ने छत्तीसगढ़ संवाद के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में संचालक जनसंपर्क श्री अजय कुमार अग्रवाल, अपर संचालक श्री जे.एल. दरियो, श्री उमेश मिश्रा, श्री संजीव तिवारी, श्री आलोक देव, श्री संतोष मौर्य, श्रीमती हर्षा पौराणिक सहित विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

जनपद पंचायत अं.चौकी में लखपति दीदी पहल अभिसरण कार्यशाला का आयोजन

मोहला। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देशानुसार गतदिवस को आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रियंवदा रामटेके की अध्यक्षता में लखपति दीदी पहल अभिसरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं जनपद पंचायत में संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग से आये हुये अधिकारियों द्वारा दी गई शासन की पहल लखपति दीदी अंतर्गत विकासखंड में 35 लखपति सीआरपी द्वारा स्व-सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाने में अन्य विभाग द्वारा अभिसरण से लाभ दिलाने के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें बिहान योजना अंतर्गत संकुलों से लखपति दीदीयों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही उनके द्वारा अपने लखपति बनने की यात्रा के विषय में बताया गया जिसमें विभागीय योजनाओं से ऋण एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। उक्त कार्यशाला में मत्स्य पालन विभाग से श्री ए.के. रजक, पशुपालन विभाग से डॉ. देवेंद्र कुमार देवांगन, कृषि विभाग से श्री तेज बहादुर कश्यप, एनआरएलएम से बीपीएम कमलेश गौरकर, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा से रितु चंद्राकर, एडीईओ श्री योगेश पिस्दा, ब्लॉक फेलो सविता साहू सभी संकुल के पीआरपी एवं स्व-सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित थे।

जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. भुरे ने गांवों का दौरा कर कार्यों का किया निरीक्षण

ठेकेदारों की बैठक लेकर मिशन के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश

मुंगेली। जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मुंगेली जिले के लोरमी विकासखण्ड के विभिन्न गांवों का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर नल जल योजना से पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने जल जीवन मिशन के ठेकेदारों की बैठक लेकर मिशन के शेष कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ जल्दी पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मुंगेली जिले के घोरबंधा, गोड़खाम्ही और तेलीखाम्ही का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा कर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने तीनों गांवों में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति, हितग्राहियों की संख्या, उपलब्ध कराए गए नल कनेक्शन, पानी टंकी की क्षमता इत्यादि की जानकारी ली और अधिकारियों को प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरपंचों से गांव की समस्याओं और उनके निराकरण के बारे में भी चर्चा की।

मिशन संचालक डॉ. भुरे ने लोरमी रेस्ट हाउस में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों की बैठक लेकर मिशन के शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी पूरी सक्रियता से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंगेली जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय, लोरमी के एसडीएम श्री अजीत पुजारी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री कुंदन राणा सहित विभागीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।

उल्लास नवभारत साक्षरता केंद्र का कलेक्टर धर्मेश साहू ने किया उद्घाटन

सारंगढ़ बिलाईगढ़। असाक्षर नागरिकों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे उल्लास नवभारत साक्षरता केंद्र सरिया का विगत दिवस कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में साक्षरता को बढ़ावा देना और समाज के हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। यह केंद्र सरिया के पीएमश्री शासकीय बालक प्राथमिक शाला परिसर में संचालित है, जहां कई बुजुर्ग महिलाएं पढ़ना लिखना सीख रही हैं।

कलेक्टर ने अपील किया कि सभी शिक्षित व्यक्ति अपने से जुड़े असाक्षर को साक्षर करें, जिससे यह कार्यक्रम निश्चित सफल होगा। यह उल्लास कार्यक्रम विशेष रूप से शिक्षा से वंचित और पिछड़े नागरिकों के लिए है। यह एक सुनहरा अवसर है। कलेक्टर ने छात्रों और शिक्षकों को इस पहल का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने बताया कि उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बच्चों बल्कि वयस्कों को भी शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यशालाओं और अभियानों के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के चेहरे में अनपढ़ और अशिक्षित होने के भाव से हुई निराशा को दूर करने की पहल है। इस कार्यक्रम के नाम के अनुरूप शिक्षित होने पर ऐसे सभी नागरिकों के चेहरे में उल्लास दिखाई देगा और अपने नाम को सार्थक करेगा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विश्वास डेयरी का किया औचक निरीक्षण

कोण्डागांव। त्यौहारों के नजदीक आते ही मिठाई विक्रेताओं द्वारा अधिक से अधिक मिठाई बनाने व विक्रय करने के चक्कर में गुणवत्ता के साथ साथ साफ सफाई में भी लापरवाही की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री डी के देवांगन द्वारा बुधवार को विश्वास डेयरी कोण्डागांव का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि विश्वास डेयरी में मिठाई निर्माण की जगह पर कचरा व गंदगी फैली हुई है। इसके साथ ही साफ सफाई का अभाव पाया गया और कमरे में विभिन्न प्रकार के सामान अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। जिस पर दुकान के संचालक को फटकार लगाते हुए उसे तुरंत साफ करने और व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और मिठाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलाकंद का नमूना लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

अशासकीय विद्यालयों के प्रधान पाठक और प्राचार्यों को अपार और परख प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के अशासकीय विद्यालयों के प्रधान पाठक और प्राचार्यों को अपार और परख प्रणाली के लिए ज़िला स्तरीय विशेष प्रशिक्षण सह-कार्यशाला आयोजित। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार करना है। पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन के ज़रिये अपार प्रणाली के माध्यम से छात्र-छात्राओं का स्थायी शैक्षणिक खाता बनाया जाएगा, जिसमें उनकी पूरी शैक्षणिक यात्रा का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। प्रशिक्षण शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेमेतरा में आयोजित किया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक संचालक श्री एस.पी. कोसले ने शिक्षकों को अपार आईडी की महत्ता और इसके उपयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली से शिक्षकों के व्यक्तिगत डेटा और अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक सूचनाओं का प्रबंधन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। इसके साथ ही, परख के संबंध में भी शिक्षकों को बताया गया, जिससे छात्रों की प्रगति का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन किया जा सके।

सहायक जिला परियोजना अधिकारी श्री सुनील कुमार झा ने कार्यशाला में अपार और परख की तकनीकी विशेषताओं के बारे में बताया। जिला मिशन समन्वयक श्री नरेंद्र वर्मा ने शिक्षकों को इन नई व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली शिक्षा के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्कूल प्रशासन और शिक्षकों के लिए छात्रों की प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।

परख प्रणाली के तहत शिक्षकों को मूल्यांकन और निगरानी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसके जरिए शिक्षण और शिक्षार्थी दोनों के प्रदर्शन का आकलन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इस प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग, डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रियाएं भी शामिल थीं, जिससे शैक्षिक व्यवस्थाएं और अधिक संगठित और प्रभावी बनेंगी।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने दीप प्रज्जवलित कर किया स्वदेशी मेला का उद्घाटन

स्वदेशी मेला का उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है - मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

कवर्धा। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेला हमारे भारत देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। स्वदेशी मेला के माध्यम से अपने देश में बने चीजों को खरीदने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वदेशी वस्तुएं आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का भाव पैदा करता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का संदेश दिया है और डिजिटल इंडिया को बढ़ाने का कार्य कर रहे है, जिससे देश मजबूत हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदेश में स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें अपने देश की समान खरीद कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना चाहिए।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि लगातार स्वदेशी मेला के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। पहले हमारा देश आर्थिक स्थिति में 11 वे नंबर पर था लेकिन आज हमारा देश 5 वे नंबर पर आ कर मजबूत हुआ है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी स्वदेशी वस्तुएं उपलब्ध है। हमें ऑनलाइन खरीदी करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उपयोग करने वाली वस्तुएं स्वदेशी हो। कवर्धा के स्वदेशी मेले में बहुत सारे स्वदेशी वस्तुओं का स्टॉल लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे। हमारा दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी को देश में बनी चीजों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।

उल्लेखनीय है कि कवर्धा जिले में पहली बार स्वदेशी मेला का आयोजन हो रहा है, जिसका आगाज 17 अक्टूबर से कवर्धा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में हुआ। स्वदेशी मेला में विभिन्न राज्यों से स्वदेशी उत्पादों के हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के अलावा लखनऊ, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्ली, पंजाब और कश्मीर तक के स्टाल की प्रदर्शनी लगाया गया है।

साथ ही प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वदेशी मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना तथा लोगों तक स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। स्वदेशी मेला को लेकर जिले के नागरिकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। स्वदेशी मेला में 150 से अधिक स्टाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच और संचालन के लिए आफिस का भव्य सेटअप बनाया गया है।

टिंकरथान में जिले के बच्चों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

- **अकलवारा स्कूल द्वितीय एवं कौंदकेरा स्कूल ने हासिल किया तृतीय स्थान**
- **कलेक्टर अग्रवाल ने बच्चों से की मुलाकात**
- **अच्छे कार्य के लिए दी बधाई, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं**

गरियाबंद। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा 28 एवं 29 सितम्बर को बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय टिंकरथान 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इसमें छात्र-छात्राएं टिंकरथान प्रतियोगिता में दिये गये थीम अर्बन एवं रूरल पर आधारित मॉडल निर्माण एवं प्रेजेंटेशन पर कार्य किया। प्रतियोगिता में राज्य भर से निजी एवं शासकीय एटीएल एवं नॉन एटीएल स्कूल से 280 टीम शामिल हुए, जिसमें से अकलवारा के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के बच्चों ने शानदार विज्ञान मॉडल प्रस्तुत कर द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल कौंदकेरा ने तृतीय स्थान हासिल किया।

पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात बच्चों ने कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल से मुलाकात की। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बच्चों को विज्ञान मॉडल पुरस्कार मिलने पर हर्ष जाहिर किया। उन्होंने बच्चों को बधाई देते हुए भविष्य में आगे बढ़ते रहने की शुभकामनाएं दी।

साथ ही पढ़ाई के अलावा विज्ञान और नवाचार के कार्यों में भी रूचि लेते हुए आगे बढ़ने प्रेरित किया। इस दौरान बच्चों ने कलेक्टर से मुलाकात कर खुशियां जताई।

श्रमजीवी पत्रकार संघ ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

खैरागढ़। प्रांतीय निर्देश पर श्रमजीवी पत्रकार संघ ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा।

अध्यक्ष आलोक श्रीवास, जितेंद्र सिंह गौर, खिलेन्द्र नामदेव, यतेंद्रजीत सिंह, प्रशांत सहारे, किशोर सोनी, रेखा झा, शिवानी परिहार, साकेत श्रीवास्तव, नीलेश यादव, जितेंद्र यादव, श्रेयांश सिंह, सन्नी यदु सहित अन्य ने पत्रकारों के विभित्र समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर मांग संबंधी ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश अब अपनी युवावस्था का 25 साल पूरा कर लगभग हर सुविधाओं से परिपूर्ण है लेकिन समाज के हर वर्ग के विकास की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला श्रमजीवी पत्रकार इससे वंचित है।

उन्होंने पत्रकार कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर पांच लाख करने, सम्मान निधि योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता का काम करने वाले साथियों को लाभ दिलाने अधिमान्यता की शर्त समाप्त करने, सम्मान निधि की राशि 15 हजार करने, पत्रकारो की सुरक्षा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा गठित का पुनर्गठन करने, एफआईआर की स्थिति में उच्च अधिकारियों से जांच, साप्ताहिक, मासिक समाचार पत्र के संपादक को अधिमान्यता देने, टोल नाका फ्री करने, विश्राम गृह में पत्रकारों के लिए आरक्षण, शहर की तरह ग्रामीण पत्रकारों को भी साल में दो बार भ्रमण करवाने, वेज बोर्ड के नियमानुसार प्रदेश के पत्रकारों व ग्रामीण संवाददाताओं को वेतन दिलवाने श्रम विभाग को प्रक्रिया प्रारंभ कराने, शासकीय विज्ञापनों में प्रदेश के अखबारों, स्थानीय चैनल को प्राथमिकता देने के अलावा रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालय, कस्बों में पत्रकारों को न्यूनतम दर पर जमीन देने की मांग की है।

संपादकीय

खत्म होता 'लाल उग्रवाद'

देश में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबूझमाड़ घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक ही लड़ाई में 31 नक्सलियों को ढेर कर हमारे आकलन को पुख्ता किया है। अबूझमाड़ ऐसा पिछड़ा और खतरनाक इलाका है कि सरकारी अधिकारी वहां जाने से पहले कांपने लगते हैं, लिहाजा उस इलाके में हमारे जांबाज सुरक्षा बलों की यह बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों तक नक्सली सिमट कर रह गए हैं। पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड सरीखे राज्यों में नक्सली बेहद उग्र और व्यापक थे, लेकिन अब उनके अवशेष ही मौजूद हैं। इन राज्यों के गरीबों, किसानों, आदिवासियों और भूमिहीनों में कोई भी भूमि-सुधार लागू नहीं हो सका है अथवा इन तबकों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। नक्सलवाद की शुरुआत इसी मकसद से हुई थी, लेकिन बाद में वे 'माओवादी उग्रवादी' बनकर ही रह गए। तो नक्सलवाद नाम की क्रांति के मायने क्या रह गए हैं? अब यह कोरी हिंसा और आतंकवाद के एक प्रारूप का नाम रह गया है। अबूझमाड़ के जंगलों में जो ऑपरेशन किया गया, वह छत्तीसगढ़ के इतिहास में 'अकेला सबसे बड़ा' माना जाएगा। यह इसलिए भी 'अभूतपूर्व' माना जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के शीर्ष कमांडरों-कमलेश और नीति-को भी मार दिया गया। यह हमारे सुरक्षा बलों की रणनीति की शानदार जीत है। नक्सलियों के सफाये के मद्देनजर यह साल 'सर्वश्रेष्ठ' के तौर पर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस साल अभी तक 202 माओवादी उग्रवादियों को मारा जा चुका है, जबकि 723 ने आत्मसमर्पण किया और 812 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरक्षा के क्षेत्र में यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। नक्सलवाद के संदर्भ में हमारे सुरक्षा ऑपरेशन की सफलता का कोई इकलौता कारण नहीं है। ऑपरेशन कई दशकों से जारी रहे हैं, लेकिन ऐसी कामयाबी नहीं मिली थी, जिसके आधार पर आकलन किया जा सके कि अब 'लाल उग्रवाद' समाप्ति के दौर में है। नक्सलियों की सोच थी कि भारत में संसदीय लोकतंत्र खत्म किया जाए। 2050 तक देश की सत्ता पर 'माओवादी चेहरा' आसीन होना चाहिए।

जिस दौर में नक्सलवाद का विस्तार हो रहा था और खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय मानता था कि 100 से अधिक जिलों में नक्सलवाद की मौजूदगी है, तब यह उम्मीद नहीं थी कि 'लाल उग्रवाद' अबूझमाड़ के जंगलों तक सिमट कर रह जाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ शानदार सफलता में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और समझ, माओवादी गढ़ के निकट अधिकतर सुरक्षा-शिविरों की स्थापना और उनके संचालन, तकनीकी सुधार के तहत ड्रोन की तैनाती और सभी क्षेत्रों में बेहतर संचारी जुड़ाव आदि का भरपूर योगदान रहा है। हमारे सुरक्षा दस्ते किसी एक बल के जवानों से नहीं बनते, बल्कि वे कई बलों का मिश्रण होते हैं और उसी ताकत से ऑपरेशन करते हैं। इन्हीं ऑपरेशनों के कारण ही नक्सली हिंसा में, 2023 में, करीब 72 फीसदी की कमी आई है। यह गिरावट देश भर में देखी गई है। हमारे मिश्रित सुरक्षा बलों के ऑपरेशन नियमित तौर पर जारी रहते हैं, नतीजतन उनका असर टिकाऊ और स्थिर रहता है। हिंसा में करीब 13 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। हमने वे हादसे भी देखे हैं, जब नक्सली हिंसा में एक साथ 76 जवान 'शहीद' कर दिए गए थे। जिस तरह नक्सलियों के शीर्ष कमांडरों और उग्रवादियों को, ऑपरेशन के जरिए, ढेर किया गया है, वह दशकों पहले इतना आसान नहीं था, क्योंकि गांवों और दूरदराज के इलाकों में नक्सलियों की समानांतर सत्ता चलती थी। वे स्कूल बनाने के भी खिलाफ थे। औद्योगिक इकाइयां तब काम कर सकती थीं, जब उग्रवादियों को पर्याप्त पैसा भेज दिया जाता था। वे क्रांतिकारी थे अथवा घूसखोरज्! बहरहाल भारत सरकार इसी सफलता से चुप होकर नहीं बैठ सकती। चुनौतियां अब भी सामने हैं। सरकार आदिवासियों को उनके अधिकार दे और स्थानीय विकास में उनकी हिस्सेदारी तय करे।

उनके प्रतिनिधित्व को मान्यता दे। नेपाल और म्यांमार से अवैध हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाए। नक्सलियों की लामबंदी अब भी जिंदा है। वे उन्हें अपना आधार बना सकते हैं, जो किसी भी वजह से सरकार से नाराज रहे हैं और खुद को 'वंचित जमात' मानते हैं। सरकार ऐसी जमातों के दिल और दिमाग को जीतने की भी भरसक कोशिश करे। जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि वे फिर से आतंकी गतिविधियों की ओर न लौटें और क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके।

नशे की बढ़ती लत से समाज खतरे में

समाज के बदलते परिवेश में कुछ अलग करने की कामना, मानसिक तनाव और बहुत से शौक ऐसे कारण हैं जो नशे के प्रचलन को समाज में बढ़ा रहे हैं। इसका ज्यादातर शिकार हमारी युवा पीढ़ी हो रही है। वर्तमान में नशा युवाओं के लिए फैशन बन गया है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नशे का हानिकारक प्रभाव न केवल नशा करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, अपितु यह पूरे परिवार और समाज को भी खोखला करने का काम करता है। एक समय हिमाचल को बदनाम करने वाले भांग, अफीम और चरस जैसे खतरनाक नशे की जगह अब चिट्टे ने ले ली है। चिट्टा वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक ड्रग्स है। हिमाचल का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां पर पुलिस द्वारा चिट्टे की बरामदगी न हुई हो, खासकर सीमांत जिलों कांगड़ा, ऊना एवं सोलन जैसे जिलों में चिट्टे का सर्वाधिक प्रकोप है, जो कि कई युवाओं के जीवन को निगल चुका है। अक्सर नशेड़ी आदमी को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फिर भी न चाहते हुए भी वे इस लत से छुटकारा नहीं पा सकते। वर्तमान में हालात ऐसे बन चुके हैं कि स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटीज में पढने् वाले विद्यार्थी नशाखोरी की चपेट में आने लगे हैं। नशा माफिया छात्रों को किसी तरह से बहला-फुसला कर नशे की लत लगा देता है और जब ये छात्र इस महंगे नशे को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं तो नशा माफिया इन बच्चों को नशा तस्करी के दलदल में धकेल देता है। अभी कुछ समय पहले ही एनआईटी हमीरपुर में कई छात्र इस नशाखोरी के चक्कर में पकड़े गए थे। आजकल आधुनिकता की दौड़ में संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार को तरजीह दी जा रही है। ऐसे में बच्चों में अकेलापन, सामाजिकता का अभाव इत्यादि के कारण बच्चों में नशे की तरफ रुचि बढ़ जाती है। अगर एकल परिवार का लडक़ा या लडक़ी नशे के जाल में फंसते हैं तो उस परिवार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है।

एक 'रतन' जो अब खो गया ...

रतन टाटा आजादी के बाद के उन उद्योगपतियों में से एक थे, जिन्होंने न केवल अपने हम उम्र और आज 40-50 साल के उम्र में जी रहे लोगों को प्रेरणा दी है। बल्कि मिलेनियर भी उनके बड़े फॉलोअर्स रहे थे।

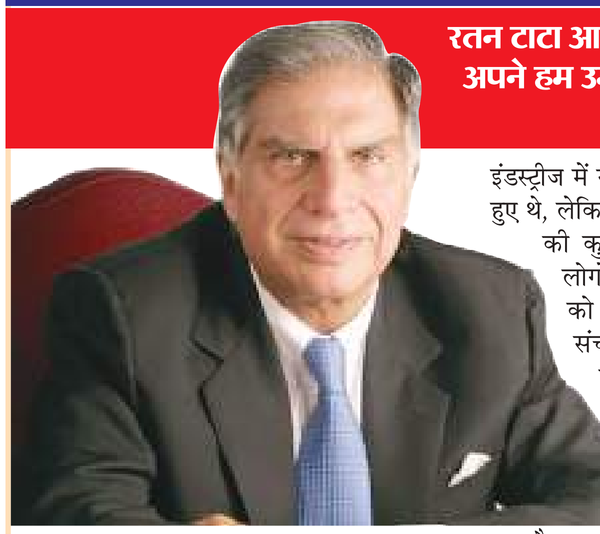

रतन टाटा सिर्फ महज नाम नहीं बल्कि एक संस्थान थे। उन्होंने कर्मयोग के जरिए यह बताया कि आप मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए अच्छी सोच के साथ बहुत आगे तक का सफर तय कर सकते हैं। उनकी यह सोच सिर्फ दिमाग या किताब के पन्नों तक कैद नहीं रही बल्कि उसे जमीन पर उतारा भी। 1991 में जब टाटा ग्रुप की कमान संभाली उस समय इस समूह का राजस्व 4 बिलियन डॉलर था और 2012 में अवकाश लिया उस वक्त इस समूह का कुल राजस्व 100 बिलियन डॉलर के पार था। यानी महज 21 साल के नेतृत्व में असाधारण कामयाबी का प्रदर्शन किया।1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में समूह में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने मार्च 1991 में ही चेयरमैन की कुर्सी संभाली, जब समूह पर पुराने लोगों का दबदबा था। अपने डिवीजनों को अर्ध-स्वायत्त साम्राज्यों के रूप में संचालित कर रहे थे, उन्होंने एक-एक करके क्षत्रपों को हटा दिया और समूह के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में सत्ता को केंद्रीकृत कर दिया।2012 में टाटा समूह ने 100 बिलियन डॉलर की बाधा को पार कर लिया था और इस तरह की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला पहला भारतीय समूह बन गया था।

टाटा ने उस वक्त ग्रुप की कमान संभाली थी जब दुनिया ने उदारीकरण की राह पकड़ी। 1991 के उस दौर में खतरे और अवसर दोनों को रतन टाटा ने समझा और भुनाया।टाटा ने सीमेंट, कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों को बेचने, सॉफ्टवेयर और स्टील जैसे मौजूदा व्यवसायों को दोगुना करने और दूरसंचार, यात्री कार, बीमा, वित्त, खुदरा और विमानन जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश करने जैसे साहसिक निर्णय लिए।

रतन टाटा आजादी के बाद के उन उद्योगपतियों में से एक थे, जिन्होंने न केवल अपने हम उम्र और आज 40-50 साल के उम्र में जी रहे लोगों को प्रेरणा दी है। बल्कि मिलेनियर भी उनके बड़े फॉलोअर्स रहे थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जबकि X पर 12.6 मिलियन फॉलोअर्स है। भारत में रतन टाटा एक ऐसा नाम रहा है जिसने आम आदमी को कार मालिक बनने का सपना दिखाया, यही नहीं उन्होंने ग्लोबल लेवल पर भारतीय कंपनियां अंग्रेजों का गुरूर तोड़ सकती है, इसका अहसास भी कराया।

उन्होंने अपने दौर में बड़ी ग्लोबल डील की थी। इसमें टाटा ने Tetley को साल 2000 में कोरस स्टील को 2007 में और जगुआर लैंडरोवर को साल 2008 में खरीदा था। यही नहीं उन्हीं के दौर में टीसीएस दुनिया में छाई और आज वह भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई है। इसके अलावा रतन टाटा देश के उन चुनिंदा उद्योगपतियों में से एक थे, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में उदारीकण का पुरजोर समर्थन किया। उनकी रिस्क लेने की क्षमता का ही असर था, कि टाटा ग्रुप दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में पहुंच गया। यही नहीं उनका एक ऐसा सपना जो उनके चेयरमैन रहते पूरा नहीं हो पाया लेकिन उनके जीवन काल में पूरा हुआ। वह था एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में वापसी। जो कभी टाटा ग्रुप की हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसे सरकार ने खरीद लिया था।

28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा को को भारत सरकार ने पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी नवाजा है। उन्होंने टाटा ग्रुप में अपना कैरियर साल 1961 में 24 साल की उम्र में शुरू किया था। उनका पहला काम टाटा स्टील में शॉप फ्लोर का ऑपरेशन मैनेज करना था। वहां से बिजनेस के गुर सीखते हुए रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। जिस समय रतन टाटा ने ग्रुप की कमान संभाली थी, उसका ज्यादा बिजनेस भारत में था। और उसकी कमाई करीब 5.7 अरब डॉलर थी। उस समय उन्होंने जेआरडी टाटा से ग्रुप की कमान मिली थी। और जब उन्होंने 2012 में करीब 21 साल के कार्यकाल के बाद ग्रुप की कमान छोड़ी थी, तो ग्रुप का रेवेन्यू 12 गुना बढ़ चुका था। और करीब 83 अरब डॉलर का ग्रुप बन चुका था। इसी तरह 2016 में साइरस मिस्त्री को कमान सौंपते वक्त, रतन टाटा की अगुआई में ग्रुप का रेवेन्यू 20 गुना बढ़ चुका था। टाटा ग्रुप के चेयरमैनशिप से वह 75 साल की उम्र में रिटायर हुए।

रतन टाटा के निधन के बाद पूरा देश शोक में है। यकीनन भारत ने एक रत्न खो दिया मगर लीजेंड कभी मरते नहीं .....

राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर उठता प्रश्नचिन्ह

नरेन्द्र पाण्डेय

दिल्ली से भाजपा की सांसद बाँसुरी स्वराज का एक बयान आया जिसमे उन्होंने कहा की INDIA अलायेंस के अंदर एसी सुगबुगाहट है कि राहुल गांधी विपक्ष के सर्वमान्य नेता नहीं है और उन्हे लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर भी नहीं रहना चाहिए । बात उठ रही है कि जो अपनी पार्टी को मैनेज नहीं कर सकते वो विपक्षी एकता को क्या मैनेज करेंगे ? 'टीएमसी' और 'आप' के कुछ सांसद, नेता , ये सवाल उठा रहे है कि राहुल का व्यवहार लीडर ऑफ अपोजिशन जैसा नहीं है । सवाल इस लिए भी उठ रहा है कि जब हरियाणा का चुनाव आपको जीत की थाली मे परोस कर दे दिया गया था तब आप हरियाणा के एक नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के भरोसे पूरा चुनाव छोड़कर सप्ताह भर के लिए विदेश चले गए थे ।

सुना तो यह भी जा रहा है की हरियाणा हार की समीक्षा बैठक मे राहुल गांधी नाराज होकर बाहर निकल आए थे और कहा की पार्टी के लोकल लीडर और कार्यकर्ताओं को इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए । इसका उन्हे एहसास होना चाहिए . लेकिन आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा है । बाँसुरी स्वराज ने कहा की विपक्ष मे एसे नेताओ की कमी नहीं है जो विपक्ष के नेता हो सकते है और यदि विपक्ष के नेता ये तय कर ले की हम इस पद को रोटैशन वाइज़ चलाएगे हालांकि यह INDIA अलायेंस का इंटरनल मैटर है मै तो सलाह दे रहीं हूँ । अब इस बयान से राहुल गांधी की कुर्सी जाएगी या बचेगी ये तो अलग विषय है लेकिन बाँसुरी स्वराज ने के मुद्दा तो उछाल ही दिया है।

हरियाणा चुनाव परिणाम से राहुल को एक झटका और लगा है। उनके झूठ की कलई खुल गई है। याद है न किस तरह लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी और उनकी टीम ने देश की जनता के सामने एक झूठ फैलाया था कि यदि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगे तो देश का संविधान बदल देगे आरक्षण को खत्म कर देंगे । जिसका थोड़ा लाभ उन्हे यूपी-बिहार चुनाव मे मिला भी । साथ ही कुछ अन्य राज्यों मे भी इसका आंशिक प्रभाव हुआ और भाजपा बहुमत से 32 सीटे पीछे रह गई । लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव ने इस झूठ को पकड़ लिया और साथ ही राहुल गांधी की विश्वसनीयता और उनकी योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया ।

21 माह में 848 सड़क हादसे, 419 ने गंवाई जान

सड़कों पर बना जानलेवा गड्डा बना कारण

बलौदाबाजार। जिले में सड़क हादसे अब गंभीर समस्या बन गए हैं। बलौदाबाजार में बीते 21 महीनों में 848 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 419 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 687 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये आंकड़े सुनकर किसी भी संवेदनशील दिल का कलेजा पिघल जाएगा, जबकि यातायात पुलिस और प्रशासन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, असली समस्या 'खराब सड़कें' हैं, जो हर दिन जानलेवा साबित हो रही हैं।

यातायात विभाग के ही अफसरों की मानें तो ज्यादातर हादसों की वजह खराब सडकें हैं। इस पर भी लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। इस वजह से ज्यादा जानों पर संकट पदा होता है। हैवी गाड़ियों के भार से लहर बन चुकी सड़कों पर थोड़ी भी रफ्तार मौत को सीधा न्यौता देता है क्योंकि बेकाबू गाड़ी को संभालना तक और मुश्किल हो जाता है जब यह लहराने लगती है। कुछ ऐसा ही हाल हम बलौदाबाजार से भाटापारा जाते वक्त देखते हैं। 24 किलोमीटर के इस मेन रोड पर सड़क कई जगहों पर एक ओर से बुरी तरह दब गई है।

सड़कों की खराब स्थिति बनी गंभीर चिंता

कुकुरदी मोड़ से आगे बढ़ने पर यह सड़क ऐसी लगती है जैसे जीवन और मौत के बीच का एक खतरनाक पुल हो। यहां दोपहिया वाहन चलाना किसी मौत के कुएं में बाइक चलाने से कम खतरनाक नहीं है।

बारिश के दिनों में जब ये नालीनुमा गढ्डे पानी से भर जाते हैं, तब सड़क की गहराई का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे भी राहगीर हादसों का शिकार होते हैं।

पीडब्ल्यूडी के अफसर हैं, जिनके कानों में जूं रेंगने का नाम नहीं लेती। हादसों की बढ़ती संख्या और सड़कों की खराब स्थिति गंभीर चिंता बन गई है। प्रशासन ने समय रहते इस समस्या का हल न निकाला, तो सड़क पर यात्रा करना लोगों के लिए जीवन-मृत्यु का खेल बना रहेगा।

मरम्मत के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी लिखा पत्र

ट्रैफिक पुलिस ने 15 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखकर सड़क की मरम्मत के लिए अनुरोध किया है। लेकिन, फिर सवाल यही है कि क्या यह उपाय काफी है? यह सच है कि बलौदाबाजार-भाटापारा मार्ग पर ओवरलोड वाहनों की आवाजाही जैसे रेत से भरे ट्रक और सीमेंट संयंत्रों की भारी मशीनें इस सड़क की बुरे हालात के मुख्य कारण हैं। रायगढ़-कोरबा रूट खतरा

रायगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा जैसे औद्योगिक शहरों से चौबीसों घंटे आने वाली भारी गाड़ियां भी बलौदाबाजार की सड़कों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने का बड़ा कारण हैं। इन गाड़ियों के साथ विद्यार्थी, व्यापारी और आम लोग भी इस रोड से गुजरते हैं। कुकुरदी बायपास से लेकर भाटापारा तक की सड़क की स्थिति बहुत खराब है।

कटघोरा वन मंडल में स्टॉप डेम निर्माण में लाखों की राशि गबन

कटघोरा। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में वन विभाग के अधिकारियों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। स्टॉप डेम निर्माण के लिए पुनरक्षित दर से राशि की मांग की गई है,जिसमें लाखों रुपए की गबन की आशंका है। मामले में मुख्य वन संरक्षक ने वन मंडल अधिकारी से जवाब मांगा है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला वन विभाग की भर्राशाही को उजागर करता है और सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाता है।

वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, कटघोरा वन मंडल में ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना के तहत स्टॉप डेम निर्माण कार्य कलेवा नाला,चेचही नाला, मनागदी नाला,साड़ामार नाला,गोलवा नाला पर कराया गया था। इस परियोजना के लिए सत्र 2018 - 19 में कैम्पा मद के अंतर्गत राशि स्वीकृत की गई थी।

अब वन विभाग के अधिकारी इन स्टॉप डेमों के लिए पुनरक्षित दर से राशि की मांग कर रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए की गबन की आशंका है। मामले में वन मंडल अधिकारी से पूछा गया है कि पहले स्वीकृत एस्टीमेट पर काम पूरा हो गया था या नहीं। वन विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि वे कागजों में काम पूरा दिखाकर लाखों रुपए निकाल रहे हैं। मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है।

मुख्य वन संरक्षक ने कहा, मामले की जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने वन विभाग की भर्राशाही को एक बार फिर से उजागर किया है और सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाया है।

पत्रकारों ने 'महासंकल्प संयुक्त महासम्मेलन' में दिखाई एकजुटता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार राजधानी रायपुर में पत्रकारिता के विभिन्न चुनौतियों को लेकर पत्रकारों ने संयुक्त पत्रकारिता महासंकल्प महासम्मेलन आयोजित किया। जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ सहित भारत के अन्य राज्यों से भी पत्रकारों की एकजुटता रायपुर में दिखी। जहाँ सभी ने एक आवाज़, एक सूर में पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार,अन्याय को देखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की माँग रखी।

ज्ञात हो कि 02 अक्टूबर राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी जयंती के दिन राजधानी के ग्रास मेमोरियल में आयोजित पत्रकार संकल्प महासभा का कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। पत्रकारों के इस महासम्मेलन में प्रदेश के 32 से भी ज्यादा पत्रकार संगठनों ने हिस्सा लिया और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित पत्रकारों के हितों से सम्बंधित अन्य मांगों को लेकर राजभवन पहुँचे और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा।

पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर संयुक्त पत्रकार महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पत्रकारों पर हमले लगातार होते आ रहे हैं। बदसलूकी, मारपीट और झूठे मामलों में फँसा कर जेल भेजने की साजिश अनवरत जारी है। छत्तीसगढ़ में पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा की सरकार है, परन्तु पत्रकारों की सुरक्षा और हक की चिंता किसी भी सरकार को नहीं है। केवल भाषणों में ही चीख-चीख कर पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है और उनकी सुरक्षा का ढिंढोरा पीटा जाता है।

वास्तव में देखा जाय तो सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पत्रकारों के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर आज पूरे प्रदेश के हजारों कलमकारों ने रायपुर के ग्रास मेमोरियल में एक मंच पर एकत्रित हो कर महासभा का रूप दिया। मंच पर पीड़ित पत्रकारों ने अपनी-अपनी आपबीती साझा की और मंचस्थ वरिष्ठ पत्रकारों ने प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की माँग की और पत्रकारों को शासन की ओर से विभिन्न सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा।

पत्रकारों के उद्बोधन पश्चात् प्रतिनिधि मंडल छत्तीसगढ़ सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर राजभवन पहुँचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दरमियान पीड़ित पत्रकारों ने भी सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपते हुए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की।

पत्रकार संकल्प महासभा छत्तीसगढ़ के इतिहास में पत्रकारों का ऐसा प्रथम महासम्मेलन है। जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त पत्रकारों की एकजूटता दिखाई दी। सभी पीड़ित पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए मंच के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई और न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि चौथे स्तम्भ कहे जाने वाले पत्रकारों की इस जायज माँग और बुलंद आवाज पर शासन कब नींद से जागेगी... ?

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ग्रास मेमोरियल में पत्रकारिता से जुड़े संगठनों की एकता का मंच देखा गया, जहां पत्रकारिता संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पत्रकारों का पहला कार्यक्रम था, जिसमें राज्य के सभी पत्रकार संगठनों की एकजुटता दिखाई दी। इस कार्यक्रम में पूर्व और वर्तमान सरकारों के कार्यकाल में शोषित पत्रकारों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों ने भी इसमें भाग लिया।

सुकमा में हुआ अंतराज्यीय पत्रकारों का महा सम्मेलन

पत्रकारों पर हुये अन्याय को लेकर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

रायपुर । बस्तर संभाग के सुकमा जिले में वरिष्ठ पत्रकार बप्पी राय, निशु त्रिवेदी, मनीष सिंह और धर्मेंद्र सिंह को 11 अगस्त को गांजा प्रकरण में षड्यंत्र पूर्वक पुलिस के द्वारा केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले को छत्तीसगढ़, तेलंगाना आध्रप्रदेश एवं ओड़िसा के पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिला था । इसी को लेकर बस्तर संभाग के सुकमा जिले में पत्रकारों के द्वारा चार पत्रकारों पर झूठी केस बनाकर कार्यवाही किये जाने एवं प्रकरण को निरस्त करने की मांग को लेकर पत्रकारों द्वारा महा सम्मेलन आयोजित की गई। इस महा सम्मेलन में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं उड़िसा के वरिष्ठ तथा कनिष्ठ पत्रकारगण उपस्थित थे। पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन

कर देश के गृहमंत्री अमित शाह के नाम सुकमा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बप्पी राय सहित सभी साथियों की ससम्मान रिहाई और संलिप्त दोषियों के खिलाफ सीबीआई जाँच की माँग की।

इस सम्मेलन में विभिन्न पत्रकार संस्था से आये पत्रकारों ने अपनी-अपनी मांग रखते हुए पत्रकार सुरक्षा के संबंध में चर्चा किया गया एवं सुकमा जिले के चार पत्रकारों को गांजा प्रकरण में थाना प्रभारी के द्वारा षडयंत्र पूर्वक वाहन में गांजा रखकर जप्त कर कार्यवाही करने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करने पर संलिप्त लोगों पर उचित कार्यवाही करने की मांग की तथा पुलिस द्वारा लगाये गये बेबुनियाद आरोप को खारिज करने की मांग को लेकर एकसाथ नजर आये। विभिन्न क्षेत्रों से आये पत्रकारों ने सुकमा के बस स्टेण्ड के समीप सभा बनाकर अपनी-अपनी मांग रखी एवं रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपकर संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। पत्रकारों ने सुकमा के बस स्टेण्ड के समीप धरना सभा के उपरांत रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन को गृहमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा।

विदित हो कि अगस्त माह में दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा के प्रतिष्ठित पत्रकार बाधी रॉय और शिवेंदु त्रिवेदी तथा सुकमा के पत्रकार मनीष सिंह और धर्मेंद्र सिंह को साजिशन फंसाकर आंध्रप्रदेश की पुलिस से कोटा के टी. आई. की संदिग्ध भूमिका से किया गया, जिसमें पत्रकारों के गिरफ्तार करवाया गया। यह षड्यंत्र और रेत माफियाओं की मिली भगत वाहनों में अवैध रूप से गांजा रखवाया।

सुकमा पुलिस ने दर्ज कर उसे जेल भेजा है, लेकिन संलिप्त पुलिसकर्मी पर एफआईआर मुख्य साजिशकर्ता टी.आई. पर अब संयुक्त बस्तर पत्रकार संघर्ष समिति बस्तर संभाग ने इस ऐतिहासिक आंदोलन में सम्मिलित होकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने और बस्तर के पत्रकारों की सुरक्षा और न्याय के लिए अवाज को बुलंद कर समर्थन मांगते हुए आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग एक साथ नजर आये।

जिला प्रेस क्लब में विधिवत चुनाव की माँग को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से रूबरू हुए जिले के पत्रकार.. मिला आश्वासन

जिला प्रेस क्लब में विधिवत चुनाव एवं विवाद निपटारा के लिए डिप्टी कलेक्टर की उपस्थिति में जल्द होगी बैठक

कवर्धा। जिला प्रेस क्लब के सदस्यों ने आज कवर्धा विधायक कार्यालय में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर जिला प्रेस क्लब में विवाद पर विस्तृत चर्चा की। क्लब के सदस्यों ने बताया कि विगत कई वर्षों से प्रकाश वर्मा स्वयंभू अध्यक्ष बने बैठे हैं और लगातार मनमानी किया जा रहा है। प्रेस क्लब में आज तक विधिवत निर्वाचन नहीं हुआ है अध्यक्ष और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा फर्जी निर्वाचन कर अध्यक्ष सहित अन्य पदों स्वयंभू बन आसीन हो जाते हैं।

सदस्यों ने प्रकाश वर्मा पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए बताया कि प्रेस क्लब में विधिवत मासिक बैठक नहीं किया जाता है और ना ही सदस्य को आए व्यय का कोई हिसाब दिया जाता है। स्वयंभू अध्यक्ष एवं कुछ पदाधिकारी द्वारा जिला प्रेस क्लब के परिसर में बने कॉन्फ्रेंस हॉल एवं पत्रकार कार्यालय को निजी फायदा के लिए बिना कोई प्रस्ताव एवं बिना सदस्यों के सहमति के ही मनमानी तरीके से किराए में दे दिया गया है। किराए से प्राप्त आय की जानकारी ली जाती है तो विरोधी होने का हवाला देकर प्रेस क्लब की सदस्यता से निकालने की धमकी दी जाती है।

सदस्यों ने उपमुख्यमंत्री शर्मा को बताया कि इसकी शिकायत एवं नए सिरे निर्वाचन कराने की मांग रायपुर पंजीयक कार्यालय एवं कलेक्टर कबीरधाम को किया गया है। उन्होंने बताया कि सदस्यों द्वारा जिला प्रेस क्लब में विधिवत चुनाव की मांग किए जाने के कारण स्वयंभू अध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना जारी किया जा रहा है कि जिला प्रेस क्लब में बैठक करना, घुसना और नाम का प्रयोग करना मना है ऐसे कृत्य पर वैधानिक कार्यवाही करने की धमकी दिया जा रहा है। सदस्यों ने आगे बताया कि कुछ 4-5 लोग प्रेस क्लब भवन में अवैध कब्जा किए हुए हैं जिससे बाकी सदस्यों को प्रशासन द्वारा पत्रकारों के लिए दिए गए भवन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

पत्रकारों को दिए भवन का उपयोग पत्रकार हित में किया जाए ना कि किराए में दिया जाए-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

सदस्यों ने श्री शर्मा से प्रेस क्लब में उपजे इस विवाद के निपटान तक भवन परिसर को सील किए जाने एवं विधिवत निर्वाचन कराने की मांग की है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रेस क्लब में विधिवत निर्वाचन एवं विवाद का पूर्ण रूप से समाधान नही होता है तब तक भवन परिसर को सील किए जाने इन सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही एक बैठक डिप्टी कलेक्टर एवं डिप्टी रजिस्ट्रार के उपस्थिति में आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष मनहरण कौशिक और चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी को जिम्मेदारी दी कि जल्द ही एक बैठक आयोजित करें जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर और रजिस्ट्रार की उपस्थिति में सारे मसले पर चर्चा किया जाए और इस विवाद का निपटारा करें। उन्होंने कहा कि अगर पत्रकारों की सुविधा के लिए भवन दिया गया है तो उसका उपयोग पत्रकारों को अपनी सुविधा के लिए किया जाना चाहिए ना कि किराए पर देना चाहिए इस पर मैं जांच कराता हूं। उपस्थित सभी सदस्यों ने उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा का आभार व्यक्त किये।

पहले खुद रक्तदान की अब दूसरी महिलाओं को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करुंगी-संगीता

बिलाईगढ़। पहले महिलाओं में रक्तदान को लेकर काफी डर था लेकिन अब सोच बदल रही है अब महिलाएं भी रक्तदान महादान के लिए पूरे उत्साह के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने आगे आ कर एक से एक मिसाल पेश कर रही है

ऐसी ही मानवता की एक मिसाल श्रीमती संगीता तरुण खटकर ने पेश की है उन्होंने नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति कि स्वरुप मां दुर्गा माता की नौव दिन उपवास के बाद बुधवार को रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की है

नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति कि स्वरुप मां दुर्गा के नौव दिन की निर्जला उपवास रहने के बावजूद रक्तदान करना साहसिक कदम है श्रीमती खटकर का ये मानवीय साहसिक कार्य समाज में नारी शक्ति को प्रेरित करेगा।

बलौदाबाजार की श्रीमती संगीता खटकर गृहणी के साथ ही बीमा सलाहकार अभिकर्ता एवं तरुण फाउंडेशन की फाउंडर है। बुधवार को उन्होंने अपने पैतृक गृह बिलाईगड में शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय में युथ रेडक्रास ईकाई,डा भीमराव अंबेडकर फोरम सारंगढ़ , चाम्पा सेवा संस्थान ?, समर्पण सेवा संस्थान रायगढ़ एवं आयुष्मान ब्लड सेंटर एंड कंपोनेंट के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया ।

श्रीमती खटकर ने बताया कि मैंने पहले खुद रक्तदान किया है अब और महिलाओं को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करुंगी इससे कुछ नुकसान नही होता यह एक पुनीत कार्य है य ह सभी दानो में सबसे अनमोल दान हैं इससे किसी के अनमोल जीवन को बचाया जा सकता है इसलिए रक्तदान के लिए सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए रक्तदान करने के बाद मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे खुशी है मेरा यह रक्त किसी के जीवन को जीवन दान देने में मदत करेगा

रक्तदान आयोजन समिति ने मुझे प्रशस्ती पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया इसके लिए सभी आयोजन समिति का हृदय से आभार व्यक्त करती हुं।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती सुनीता कोसले युथ रेडक्रास सोसायटी प्रभारी पंकज साहु बिलाईगड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ प्रकाश कुर्रे समर्पण सेवा संस्थान से मालिकराम जायसवाल आदित्य कम्प्यूटर एज्युकेशन क्लास संचालक बिलाईगढ तुलसी आदित्य भूतपूर्व सैनिक कमल किशोर महाविद्यालय के विद्यार्थीगण शिक्षकगण एवं समाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।।

ग्रामीणों को दो माह से राशन अप्राप्त

राशन दुकान संचालनकर्ता समूह की पंजीयन निरस्त करने की मांग

बिलाईगढ़ । अनुविभाग मुख्यालय बिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत मिरचिद के ग्रामीणों को दो माह से राशन नहीं मिलने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।

प्राप्त समाचार के अनुसार ग्राम पंचायत मिरचिद के ग्रामीणों को विगत दो माह से राशन नहीं मिलने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त पंचायत में मां दुर्गा स्व सहायता समूह एवं उनके सेल्समैन के द्वारा राशन दुकान का संचालन किया जाता है इनके सेल्समैन सुमार साय के द्वारा महीना के प्रारंभ में ही ग्रामीणों से फिंगरप्रिंट ले लेता है और राशन दो माह बाद देता है और अभी वर्तमान में सितंबर एवं अक्टूबर का चावल राशन नहीं मिलने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

ग्रामीणों की शिकायत पर भाजपा मंडल महामंत्री राधा राकेश ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों के साथ इसकी लिखित शिकायत अनुभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ स्निग्धा तिवारी से कर उक्त स्व सहायता का समूह का पंजीयन निरस्त करते हुए ग्रामीणों को हर माह राशन दिलवाने की मांग किया है। शिकायतकर्ताओं में प्रमुख रूप से जीतराम, मोहनलाल, सनी, सुखीराम ,नरेंद्र, लग्नसाय ,मंगल, बजरंग केवट, धर्म, तेजराम, जितेंद्र, परदेसी, मदनलाल, खिकबाई, मंगली, आदि ग्रामीणों ने हर माह राशन दिलवाने की मांग किया है।

कबाड़ियों का पत्रकारों पर हमला, सूरजपुर के बाद अब राजधानी भी सुरक्षित नहीं

रायपुर ! टाटीबंध से विलासपुर जाने वाले बायपास रोड पर HP पेट्रोल पंप से लगा हुआ एक यार्ड है जहां लोहा काटकर बेचने की सूचना कुछ पत्रकारों पर मिली जिसकी छानबीन करने कुछ पत्रकार उस यार्ड पर पहुंचे। पत्रकारों ने उनसे बात करनी चाही लेकिन उनके द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया और पत्रकारों द्वारा मौके पर ही वीडियो बनाया गया जहां एक वर्कर गैस कटर से लोहा काट रहा था। इस यार्ड में करीब 20 से 25 वर्कर मौजूद थे, जिसका वीडियो भी ट्रक पर चढ़कर लोहा काटते हुए बनाया गया। इसके बाद यार्ड का ही एक मालिक बाहर आया और अभद्र गालीगलौच कर डंडे से पत्रकारों पर वार कर दिया, जहां एक महिला पत्रकार बेहोश होकर गिर पड़ी फिर भी उस यार्ड मालिक द्वारा लगातार डंडे से सभी पत्रकारों को मारना शुरू कर दिया। पत्रकारों ने कहा भी कि हमको सूचना मिली है आप बात करिए झगड़े लड़ाई की कोई बात ही नही है लेकिन उस यार्ड मालिक द्वारा पत्रकारों की कोई बात नही सुनी गई और लगातार लकड़ी के मोटे दंडों से सभी पत्रकारों पर वार किया गया और महिला पत्रकार का मोबाइल भी यार्ड मालिक द्वारा छीन कर रख लिया गया और यह धमकी भी दी गई कि दुबारा यहां आए तो जान से मारकर यही गाड़ दिया जायेगा।

वही इस मामले की सूचना कबीर नगर थाने में दी गई तो उनके द्वारा यह मामला आमनाका थाना क्षेत्र अंतर्गत बताया गया और जब आमानाका थाने गए तो वहां 2 साथियों को मुलायजा के लिए एम्स हॉस्पिटल भेजा गया फिर उनके द्वारा बताया गया कि यह मामला उरला थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। जब पत्रकार और उनके साथियों ने उरला थाना प्रभारी को इसकी सूचना देते हुए आवेदन लिख कर दिया गया तो उनके कोई सुनवाई नही की गई उल्टे थाना प्रभारी द्वारा मामले का सेटलमेंट करो नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है कहकर पत्रकारों का आवेदन स्वीकार थाना प्रभारी द्वारा नही लिया गया और यह भी कहा कि आवेदन से पत्रकार शब्द को हटाओ। जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत भी इस मामले से जुड़ी हुई है।

महिला पत्रकार का मोबाइल थाने में आकर यार्ड के ड्राइवर द्वारा दिया गया, लेकिन ड्राइवर से भी कोई पूछताछ थाने में नहीं की गई और उसे मोबाइल लेने के बाद वापस भेजा-

बता दें कि महिला पत्रकार जिसका मोबाइल छीना गया था उसे वापस करने जब यार्ड का ड्राइवर थाने पहुंचा तो उसे भी मोबाइल लेकर थाने से वापस भेज दिया गया और कोई भी पूछताछ यार्ड ड्राइवर से थाने में नही की गई।

इस बात से यह भी स्पष्ट जाहिर है कि पुलिस प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है, और उनके भी संरक्षण में यह कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। उरला थाना में सुनवाई नही होने के बाद अब सभी पत्रकार रायपुर SP से मामले की शिकायत भी की गई बताया जा रहा है।

बीएसपी प्रबंधन और निर्माणाधीन कंपनी जगन्नाथ पैलेट एंड पावर के खिलाफ 500 मजदूरो ने खोला मोर्चा

ठेकेदार के द्वारा की जा रही सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन की अनदेखी

बालोद। जिले के लौहनगरी के नाम से पहचान बनाने वाले दल्लीराजहरा में भिलाई इस्पात संयत्र अंतर्गत नवनिर्मित पैलेट एंड पावर प्लांट के मजदूरों ने बीएसपी प्रबंधन और निर्माणाधीन कंपनी जगन्नाथ पैलेट एंड पावर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वही मजदूर निर्माण कार्य को बंदकर प्लांट के सामने धरने पर बैठ गए है। पूरे मामले को लेकर आंदोलन कर रहे मजदूरों कि माने तो जगन्नाथ पैलेट प्लांट कम्पनी के प्रबंधन द्वारा लगातार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मजदूरों को श्रम कानून के तहत निर्धारित 6 घंटे के बजाय 8 घंटे काम लिया जाता है। यही नहीं कंपनी द्वारा यहां काम कर रहे मजदूरों के सुरक्षा को लेकर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसी के चलते बीते दिनों दो मजदूर लोमेश्वर मसीह एवं योगेश बारेझर करीब 60 फ़ीट की ऊंचाई पर काम करते समय नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद भी प्रबंधन द्वारा घायल मजदूरों को समुचित इलाज सुविधा उपलब्ध नही करने के चलते मजदूरों द्वारा अपने साथियों का इलाज दल्लीराजहरा के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। मजदूर सुरेंद्र कुमार बंसोड़े ने बताया कि एक मजदूर का हड्डी टूट गया है, और एक का पैर के घुटने की हड्डी टूट गई है। तहसीलदार, टीआई भी धमकी देकर गए है। न ही प्रशासन और न ही बीएसपी मैनेजमेंट मजदूरो का साथ दे रहा हैं। मैनेजमेंट तो मजदूरो पर ही दबाव बनाता जा रहा है लगातार। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा ही अड़ियल रवैय्या रहा तो हमारा आंदोलन और बढ़ता जाएगा। प्रबंधन के लगातार उदासीनता से नाराज करीब 500 मजदूर अनिश्चित कालीन आंदोलन पर चले गए है मजदूरों का मानना है कि जब तक प्रबंधन द्वारा उन्हें समुचित सुविधा उपलब्ध नही कराई जायेगी तब तक मजदूर काम पर नहीं लौटेंगे।

सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन की अनदेखी–

संबंधित ठेकेदार के द्वारा सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन की अनदेखी की जा रही है, सुरक्षा मानकों के नाम पर सिर्फ मजदूरो की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा हैं, जिसमें बीएसपी प्रबंधन भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और न किसी प्रकार की कार्यवाही। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि बीएसपी प्रबंधन की ठेकेदार से मिलीभगत हैं। बिना सेफ्टी बेल्ट के मजदूर ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। जिसके कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं। करोड़ों की लागत से बन रहे प्लांट में काम कर रहे मजूदरों की सुरक्षा का जिम्मा ठेकेदार व बीएसपी प्रबंधन का है। लेकिन उन्हें मजदूरों की सुरक्षा से कोई लेना–देना नहीं है। इतने दिनों से माइंस के अंदर काम कर रहे किसी भी मजदूर का गेट पास नहीं बनाया गया है।

कलेक्ट्रेट जनदर्शन में ग्रामीण मजदूर कर चुके है शिकायत–

आपको बता दे एक माह पूर्व ही इस कंपनी में कार्यरत क्षेत्र मजदूर के जिसमे धोबेदंड के आश्रित ग्राम कोडेकसा, झीकाटोला, दर्रेकसा और कुंजामटोला के ग्रामीणों ने बालोद कलेक्ट्रेट में कम्पनी प्रबंधन के खिलाफ शिकायत किया था। जिसमे कम्पनी पर यहां काम कर रहे ग्रामीण मजदूरों को गेट पास ट्रेनिंग उपलब्ध नही करने की शिकायत की गई थी। जिसके चलते इन मजदूरों को समुचित सुविधा नही मिल पा रही हैं। वही हाल ही में हुए हादसे ने मजदूरों के शिकायत पर मुहर लगा दी। वही मामले को लेकर जब मीडिया द्वारा कम्पनी के प्रबंधक से बात करने का प्रयास किया तो प्रबंधक ने मीडिया से मिलने से ही मना कर दिया गया। बहरहाल मजदूरों का यह आंदोलन आगे क्या रुख इख्तियार करती है, यह देखना होगा।

बीएसपी के अफसरों को देखने तक की फुर्सत नहीं–

कार्यरत ग्रामीण मजदूरो को सुरक्षा ट्रेनिंग नहीं दी गई हैं। ए–फार्म रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। मजदूरों से 8 की जगह 12 घंटे काम लिया जा रहा है। इस दौरान बीएसपी प्रबंधन का अड़ियल रवैय्या सामने आया है। और यह आज की बात नहीं है, बीएसपी प्रबंधन के द्वारा लगातार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाएं से उन्हें वंचित किया जा रहा है। बीएसपी प्रबंधन ठेकेदारों से मिलीभगत कर मजदूरो का अहित में करने में लगा हुआ है। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने कहा है कि ठेकेदार मनमानी कर रहा है, 60 फीट ऊंचाई में मजदूर बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए काम कर रहे है। इसे देखने बीएसपी के अधिकारियों को फुर्सत नहीं है।

मनमानी के विरोध में 500 मजदूर धरने पर बैठ गए–

ठेकेदार की मनमानी व अधिकारियों की अनदेखी के चलते विरोध में गुरुवार से लगभग 400 मजदूर धरने पर बैठ गए। यह सिलसिला शनिवार तक अनवरत जारी रहा। मजदूर सुरेंद्र कुमार हंसर, नमन बंसोड़े, विकास कुमार साहू का कहना है कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहा है। सुरक्षा ट्रेनिंग नहीं कराया गया है। वेतन भुगतान कर मस्टर रोल में हस्ताक्षर नहीं कराया जाता है। मजदूरो की माने तो जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। मजदूरो ने आगे बताया कि उन्हें धोखे में रखकर काम करवाया जा रहा है, प्लांट बता फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। न आज तलक रजिस्ट्रेशन हुआ है।

अशासकीय विद्यालयों के संचालकों एवं प्राचार्यों का नोडल प्राचार्य नरेन्द्र कुमार साहू ने लिया आवश्यक बैठक

बिलाईगढ़। सेजेस विद्यालय बिलाईगढ़ में नरेन्द्र कुमार साहू प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलाईगढ़ के द्वारा अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें नोडल प्राचार्य द्वारा सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालन के संबंध में जानकारी ली गई और स्कूलों के संचालन के संबंध में आ रही दिक्कतों को दूर करने का उचित निर्देश दिया गया, साथ ही शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर मांगी जाने वाली जानकारियों को समय पर भेजे जाने का निर्देश दिया गया, ताकि उच्च कार्यालयों तक जानकारी समय पर भेजी जा सके।

नोडल प्राचार्य ने आगे कहा कि बच्चों के बेहतर शिक्षा पर सभी संचालकों को ध्यान देना चाहिए। विद्यालय के सफल संचालन में मुख्यतया 20 बिन्दुओं के अंतर्गत स्कूलों का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए सभी बिन्दुओं पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया। उन्होंने आगे बताया कि शासन की ओर से विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके तहत विद्यालयों का ग्रेडिंग भी किया जाना है। पढ़ाई के साथ–साथ बच्चों को खेलकूद, स्काउट/गाइड, रेडक्रॉस, पर्यावरण और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना है। प्रत्येक शनिवार को 2 घंटे इन सभी इवेंट से संबंधित बच्चों की क्लास लगाए जाने की बात कही। विद्यालयों में नियमित रूप से प्रैक्टिकल कराई जाए। नोडल प्राचार्य ने सभी संचालकों को सहयोग की भावना से शासन के मंशा के अनुरूप विद्यालय का संचालन करने का निर्देश दिया।

बैठक में सागर पब्लिक स्कूल बिलाईगढ़, ज्ञान–विज्ञान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलाईगढ़, सरस्वती शिशु मंदिर बिलाईगढ़, ममता ज्ञान मंदिर बिलाईगढ़ और टैगोर शिशु निकेतन बिलाईगढ़ के प्राचार्य और संचालक गण उपस्थित थे।

> बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अध्यापन कार्य कराया जाना है, साथ ही बच्चों के प्रायोगिक कार्य पर भी ध्यान देना है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बिलाईगढ़ के स्कूलों का अलग से पहचान बन सके, जिसमें अशासकीय विद्यालयों का भी सहयोग आवश्यक है।
>
> **नरेन्द्र कुमार साहू**
> **नोडल प्राचार्य**
> स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय
> उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलाईगढ़

सरपंच स्वयं शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर पद का दुरुपयोग कर रहे

लंबे समय से जांच कार्यवाही में विलम्ब का उठा रहें फायदा

कसडोल। ग्राम विकास कार्यों में भ्रष्टाचार कर गुणवत्ता हिन निर्माण कार्यों को जांच कार्यवाही में पूरे करने आदेश की 01 वर्ष से अधिक होने और वर्तमान 16.10.2024 को जांच हुए मामले सामुदायिक भवन, नवीन जोड़ा जैतखाम निर्माण सौंदर्यकरण, मिनीमाता प्रतिमा स्थापना एवं सौंदर्यकरण, पुलिया निर्माण कार्य सत्र 2021–22 में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मद से स्वीकृति में निर्माण एजेंसी दीपेंद्र कुमार जाटवर सरपंच ग्राम पंचायत परसाडीह द्वारा पूर्ण अधूरे कार्य को पूर्ण नहीं करा।

पहले ही मूल्यांकन सत्यापन कर आहारण कर ली राशि

पंचायती राज्य अधिनियम के धारा 56 का उलघन कर दिनांक –12.12.2023 से सामुदायिक भवन की चाबी अपने संरक्षण में लेकर नियम विरुद्ध द्वेष रख निर्माण विकास कार्य में पहल करने वालों को अतिक्रमण के नाम पर जबरन कई बार नोटिस काट किया जा रहा शासन प्रशासन की नियमो की अवहेलना।

उक्त निर्माण कार्य हुए उस उद्देश्य में सामाजिक धार्मिक पत्रकारिता कार्य संचालन में सरपंच उच्च अधिकारियो जनप्रतिनिधियों की आदेशों की कर रहें अवहेलना। जिस संबंध में अनेकों बार जांच शिकायत के बावजूद द्वेष रख सरपंच अपने ग्राम विकास में किए भ्रष्टाचार और शासकीय भूमि में किए अतिक्रमण पदीय कर्त्तव्य की दुरूपयोग की लगातार जांच कार्यवाही समाचार में प्रकाशित को लेकर नियमो का उलघन कर द्वेष भावना निभाने कुकृत्य कार्य कर रहें हैं।

जिसका जमीनी हकीकत किसी से नहीं छिपा हैं। मौके पर यदि देखने तो और बड़ी खुलासा सरपंच की ग्राम विकास में किए अनियमितता की मामले सामने आ जाएगा।

शिक्षक कांग्रेस संघ जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ की भटगांव बैठक में अनेक प्रस्ताव पारित

बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस संघ जिला इकाई सारंगढ़–बिलाईगढ़ की एक महत्वपूर्ण बैठक संघ के प्रांतीय सचिव एवं सेजेस बिलाईगढ़ के प्राचार्य नरेन्द्र कुमार साहू एवं जिलाध्यक्ष कामता प्रसाद साहू की उपस्थिति में भटगांव में आयोजित की गई, जिसमें शिक्षक हितों से संबंधित अनेक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित चर्चा करते हुए सहायक शिक्षक संवर्ग से कार्य प्रारम्भ करने वाले शिक्षकों को त्रिस्तरीय वेतनमान/समयमान वेतनमान/क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त करने के लिए

विशेष रूप से चर्चा किया गया तथा रणनीति तैयार की गई। शीघ्र ही माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट पिटीशन दायर कर अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने तथा शासन से भी लगातार प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से संवाद जारी रखने, छूटे हुए शिक्षकों की सेवा पुस्तिका से संबंधित कार्य पूर्ण कराने के लिए आगामी 28 अक्टूबर से पुनः शिविर लगाए जाने की मांग करने, निकट में सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षकों की स्वत्वों का समय पर निपटारा कर सेवा निवृत्ति दिनाँक को ही क्लैम का भुगतान करने एवं शिक्षक संवर्ग के अन्य हितों के संबंध में दिनाँक 21/10/2024 दिन सोमवार को विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ से परिचर्चा कर ज्ञापन सौंपे जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस बैठक में प्रमुख रूप से संघ के प्रांतीय सचिव एवं सेजेस बिलाईगढ़ के प्राचार्य नरेन्द्र कुमार साहू, जिलाध्यक्ष कामता प्रसाद साहू, ब्लॉक अध्यक्ष अश्वनी जाटवर, तहसील अध्यक्ष भटगांव फिरतराम सायतोड़े, तहसील अध्यक्ष बिलाईगढ़ कुमारी बाई साहू, तहसील उपाध्यक्ष भटगांव राजेंद्र राय, जिला उपाध्यक्ष तेज प्रकाश भारद्वाज, सेजेस भटगांव के प्राचार्य गिरजा शंकर धीवर, चंद्रशेखर सारथी, फणेन्द्र नेताम, भगवान प्रसाद दुबे, जयंतीलाल कुर्रे एवम कुर्रे मैडम प्रधानपाठक पूर्व मा. शाला गोविंदवन सहित बड़ी संख्या में शिक्षक/शिक्षिकाएँ एवं सदस्य उपस्थित थे।

टोल फ्री नंबर 07713505050 और वेबसाइट में उपलब्ध है श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी

कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र का टोलफ्री नंबर संचालित है। इस सहायता केंद्र के दूरभाष नंबर 07713505050 पर फोन करके कोई भी नागरिक श्रम विभाग की योजनाओं और श्रमिकों को दी जाने वाली सामग्री वितरण, छात्रवृत्ति चिकित्सा आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर सातों दिन 24 घंटे संचालित किया जा रहा है। विभाग की वेबसाइट श्रमेवजयते डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन में भी सभी जानकारी उपलब्ध है, इसका भी अवलोकन कर जानकारी लिया जा सकता है। टोलफ्री और वेबसाइट दोनो में श्रम विभाग की योजना, पात्रता, लाभ, दस्तावेज, योजना की वर्तमान स्थिति, आवेदन कहां करें आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

श्रम विभाग की योजनाएं

श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक से जुड़ी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता सहित विभिन्न योजनाएं शामिल है।

ओलंपियन मनु भाकर ने परिवार सहित बारनवापारा अभ्यारण्य का किया भ्रमण

बलौदाबाजार। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 02 मेडल जीत कर इतिहास रचने वाली निशाने बाज एवं ओलंपिक विजेता मनु भाकर 27 वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता 2024 के समापन समारोह में शामिल होने राजधानी रायपुर पहुंची। सुश्री मनु भाकर ने बलौदाबाजार – भाटापारा जिले के प्रसिद्ध बारनवापारा अभ्यारण्य में सपरिवार भ्रमण किया।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बलौदाबाजार – भाटापारा जिले के प्रसिद्ध बारनवापारा अभ्यारण्य में मनु भाकर ने अपने परिवार के साथ भ्रमण किया। उन्होंने बारनवापारा अभ्यारण्य के घने जंगलों एवं वन्यप्राणियों को स्वच्छंद विचरण करते देख कर प्रसन्नता जाहिर की और वन विभाग द्वारा वन्य जीवों और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आते हुए,यह अब तक का सबसे अच्छा अनुभव रहा है, प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वनों के संरक्षण के महत्व को जाना है। इस अभ्यारण्य में स्वच्छ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। यह मेरे लिए अविस्मरणीय है,मैं यहां दोबारा आना चाहूंगी।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से राजू अगसिमनी, मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त मयंक अग्रवाल,वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार, बारनवापारा अभ्यारण्य अधीक्षक आनंद कुदरया सहित बारनवापारा अभ्यारण्य के समस्त स्टाफ उपस्थित रहें।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा का वर्चुअल उद्घाटन

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा अब हवाई सेवा से जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को वाराणसी से मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा का वर्चुअल रुप से लोकार्पण किया। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका सहित मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य शामिल हुए।

80 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ मां महामाया एयरपोर्ट

मां महामाया एयरपोर्ट, अंबिकापुर में लगभग 80 करोड़ की लागत से कार्य किए गए हैं। दरिमा हवाई पट्टी का निर्माण वर्ष 1950 में हुआ था, इसे प्रारंभिक दौर में डब्ल्यूबीएम सतह से निर्मित किया गया था, जिसकी लंबाई 1200 मीटर थी। यह हवाई पट्टी अम्बिकापुर शहर से 13 किमी की दूरी पर दरिमा ग्राम में निर्मित है। इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 365 एकड़ है और यह हवाई पटटी समुद्र तल से 1924 फीट ऊंचाई में स्थित है।

हवाई अड्डे के विकास के लिए 46.27 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को जारी की गई, जिसके तहत लोक निर्माण विभाग के ने दिसंबर 2021 से उन्नयन कार्य तीन सीव्हीएफआर के अनुरूप शुरू किया। लोक निर्माण विभाग की ओर से अप्रैल 2023 को कार्य को पूर्ण कराकर लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया, जिसके तहत डीजीसीए ने मई 2023 को निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए डीजीसीए ने 15 मार्च 2024 को एरोड्रम लाईसेंस जारी किया। रनवे को लम्बाई 1500 मीटर से बढ़ाकर 1800 मीटर किया गया।

रनवे की लम्बाई 1500 मीटर से बढ़ाकर 1800 मीटर किया गया। रनवे के मजबूतीकरण के लिए पीसीएन को बढ़ाकर 25 किया गया जिसे एटीआर 72 के अनुरूप किया गया। नये एपरोन को 110×127 मीटर का बनाया गया, जो कि एक साथ दो एटीआर 72 हवाई जहाज को खड़ा करने के लिए उपयुक्त है। इसके साथ आईसोलेशन वे, दोनों तरफ आरईएसए एवं 25×150 मीटर के दो टैक्सी-वे का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही पैरीमीटर रोड एवं अन्य एप्रोच रोड का डामरीकरण कार्य कराया गया। पूर्ण क्षेत्रफल लगभग 8 कि.मी. की लम्बाई में बाउण्ड्रीवाल की ऊंचाई 1.5 मीटर से बढ़ाकर 3.2 मीटर की गई। सारे आंतरिक मार्गों का डामरीकरण एवं रोड फर्नीचरिंग एवं मार्किंग का कार्य कराया गया।

टर्मिनल भवन का उन्नयनीकरण 20 यात्रियों से बढ़कर 72 यात्रियों के अनुरूप किया गया। एटीसी ऑफिस, एमईटी ऑफिस, एसीसीआर रूम, फायर स्टेर, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम अन्य अधोसंरचना के कार्य कराये गये हैं।

रायपुर, दुर्ग स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहा कायाकल्प

रायपुर। रेल मंत्रालय के महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने हेतु 'अमृत भारत स्टेशन' योजना के अंतर्गत स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के 15 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है । (1) भाटापारा, (2) भिलाई पावर हाउस, (3) तिल्दा-नेवरा, (4) बिल्हा, (5) भिलाई, (6) बालोद, (7) दल्ली राजहरा, (8) भानुप्रतापपुर, (9) हथबंद, (10) सरोना, (11) मरोदा, (12) मंदिर हसौद, (13) उरकुरा, (14) निपनिया, (15) भिलाई नगर, साथ ही रायपुर, दुर्ग स्टेशनों लगभग 482.48 करोड़ राशि के बज़ट से मेजर रिडेवलपमेंट किया जा रहा हैं। इन योजनाओ का मकसद आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता के साथ मौजूदा सुविधाओं के अपग्रेडेशन पर भी काम करना है । चरणबद्ध तरीके से इन कार्यों को पूर्ण किया जाएगा।

रायपुर स्टेशन को यात्रियों के अनुकूल सर्वसुविधायुक्त बनाने हेतु भव्य प्रवेश एवं विकास द्वार, यात्रियों के आवागमन एवं निकास के लिए सुगम पथ ,10 टिकट बुकिंग विंडो, बेहतरीन प्लेटफार्म सरफेस, 300 किलोवाट पावर सोलर सोलर पैनल युक्त ऊर्जा संरक्षण, प्रत्येक प्लेटफार्म पर 26 कोच इंडिकेशन बोर्ड, 74 टॉयलेट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 6 मीटर चौड़े तीन फुट ओवर ब्रिज 40 वाटर कूलर 42 लिफ्ट, 3512 स्क्वायर मीटर पार्सल एरिया, 12075 स्क्वायर मीटर प्लेटफार्म शेल्टर, 10 यात्री आरक्षण सुविधा काउंटर, 16 एस्केलेटर लगाए जाते हैं। रिजर्व लॉज, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब, कोनकोर्स एरिया, बस्तर छत्तीसगढ़ी आर्ट से सुसज्जित होगा रायपुर स्टेशन विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं से उन्नत होगा रायपुर स्टेशन। वर्तमान समय में रायपुर स्टेशन पर लगभग 50हजार यात्रियों का आवागमन होता है। भविष्य में यात्रियों की संख्या और बढ़ाने को देखते हुए स्टेशन डेवलपमेंट में यात्री सुविधा उन्नत की जा रही है। ये सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जाएंगे ।

RAIPUR JN. RAILWAY STATION : CONCOURSE VIEW

कचरे में पड़ी मिली भूपेश बघेल की तस्वीरें

दंतेवाड़ा। जिले से महिला बाल विकास विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां बच्चों के लिए भेजी गई मूंगफली चिक्की विभाग के सरकारी गोदाम में ही सड़ गई. मालूम हो कि सरकार की 'सुपोषण अभियान' के तहत ये मूंगफली चिक्की 3 से 6 साल तक के बच्चों को पोषण के लिए बांटी जाती है. इसके हर पैकेट की कीमत 5 रुपये 85 पैसे होती है. लेकिन कुआकोंडा ब्लॉक में विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते इस अहम योजना का लाभ नौनिहालों तक नहीं पहुंच सका. बताया जा रहा है कि ये मूंगफली की चिक्की 90 दिनों तक ही खाने लायक रहती है. उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है. ऐसे में ताज़ा मामले में हजारों पैकेटों को एक्सपायर होने के बाद जलाकर स्वाहा कर दिया गया. मामले में एक और हैरान करने वाली बात ये है कि गोदाम के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी कई तस्वीरें कचरे में पड़ी मिली.

बताते चले कि दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक में 150 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र है जहां रोजाना सैकड़ों आदिवासी बच्चों को सुपोषण योजना के तहत मूंगफली चिक्की दी जानी थी. लेकिन मार्च महीने की आई चिक्की अक्टूबर तक नहीं बांटी गई.... और समय पर न बांटे जाने से हजारों चिक्कियां गोदाम में ही पड़े-पड़े सड़ गई. इस लापरवाही का खामियाजा आदिवासी बच्चों को उठाना पड़ा जो इस योजना से वंचित रह गए. लापरवाही का ये मामला महिला बाल विकास विभाग की लापरवही को उजागर करता है. जहां सरकारी वादों का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता और ये योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह जाती हैं. मामले में और भी चौंकाने वाली बात यह रही कि के बाहर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़ियाकी सैकड़ों तस्वीरें कूड़ेदान में पड़ी मिलीं.

ये तस्वीरें उस समय आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटी जानी थीं लेकिन इन्हें भी लापरवाही के चलते नहीं बांटा गया. यह स्थिति दिखाती है कि जिन योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं... उन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है ? ऐसे में इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता. गोदाम के अंदर का हाल तो और भी बुरा था. गर्भवती और शिशुवती माताओं के लिए भेजा गया रेडी टू ईट फूड और खेलने के भी सामान बेतरतीब ढंग से पड़े हुए थे. गोदाम में व्यवस्था पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं।

छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है, जब उन्हें 'राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज' प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह विशेष ध्वज देश के चुनिंदा राज्यों की पुलिस इकाइयों को दिया जाता है, जो 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल मोर्चे पर साहस और दृढ़ता के साथ कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए यह सम्मान अर्जित किया है, जो उनकी उत्कृष्ट सेवा का प्रमाण है।

इस सम्मान के साथ, पुलिस बल के जवान इस ध्वज की प्रतिकृति को अपनी वर्दी पर प्रतीक चिन्ह के रूप में धारण करेंगे, जो उनके शौर्य और सेवा का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति ध्वज किसी भी पुलिस या सैन्य बल के लिए सर्वोच्च मान्यता मानी जाती है और यह छत्तीसगढ़ पुलिस की निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और परिश्रम की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना को दर्शाता है।

यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण: मुख्यमंत्री साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण है। हमारे जवानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी नक्सलियों के खिलाफ सफलता प्राप्त की है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। यह ध्वज हमारे पुलिस बल के हौसले को और भी ऊंचा करेगा , उन्हें राज्य की सुरक्षा और सेवा के लिए और प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री साय ने पुलिस बल को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि उन बहादुर जवानों के प्रति एक आदर है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना राज्य की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ की जनता को भी गर्व का अवसर प्रदान किया है, जो राज्य की पुलिस की सेवा और समर्पण का सम्मान करती है।

अब ट्रेनों में ले सकेंगे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ़

रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को निर्देश

रायपुर। रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को छत्तीसगढ़ी व्यंजन को अपने मैन्यु शामिल करने के निर्देश दिया है। जिसके कारन अब छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में अब यात्री चीला, फरा, अनरसा जैसे व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे इस निर्देश के बाद आईआरसीटीसी ने प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा, चीला, मुंगौड़ी, बरा, गुल गुल भजिया, सोहारी, ठेठरी, खुरमी, चौसेला और लड्डू उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही यात्रियों को यह सुविधा मिलने लगेगी।

रायपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना 130 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। अक्सर यात्रियों की शिकायत मिलती है कि रेलवे की खानपान सूची में यात्रियों को उनकी पसंद का नाश्ता और भोजन नहीं मिलता है। इस वजह से सफर के दौरान यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। पिछले महीने ही रेलवे अधिकारियों व छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ हुई बैठक में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को लंबी दूरी की ट्रेनों में उपलब्ध कराने की मांग उठी थी।

खानपान सेवा को बेहतर बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने सांसदों और यात्रियों की मांग के आधार पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की सूची तैयार की है। अधिकारियों के मुताबिक जिन ट्रेनों में खानपान के पैसे टिकट में ही शामिल रहते हैं उनमें कीमत में बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी सूची के आधार पर दिए जाने वाले खानपान एवं ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति रहेगी। इनके दाम एमआरपी से अधिक नहीं होंगे। वहीं सबसे अधिक बिकने वाले जनता भोजन के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। मधुमेह रोगियों एवं शिशु आहार भी मांग पर ट्रेन में ही उपलब्ध कराया जाएगा।

डॉ सलीम राज बने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष

रायपुर (लाईफ वर्सिटी)। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के बैठक में बोर्ड के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से डॉ. सलीम राज को राज्य वक्फ बोर्ड का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया।

राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि वक्फ बोर्ड अपने उद्देश्यों के अनुरूप काम करें। इसके लिए मुतवल्लियों से चर्चा कर वक्फ बोर्ड की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, भू-माफियाओं एवं अतिक्रमणकारियों से वक्फ सम्पत्तियों को सुरक्षित करने के साथ ही वक्फ की योजनाओं का सीधा लाभ सामाजिक एवं कमजोर वर्ग के शैक्षणिक विकास के लिए किया जाएगा।

डॉ. सलीम राज ने राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यगण, मुतवल्ली एवं मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिकों ने डॉ. सलीम राज को बधाई और शुभकामनाएं दी।

चुनौती पूर्ण जिम्मेदारी मिली है. पार्टी और सदस्यों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा. मैं ऐसा कार्य करना चाहूँगा जिससे कौम का भला हो और पार्टी का भी नाम हो.

साइंस कॉलेज मैदान किनारे बने चौपाटी को हटाने का निर्देश

रायपुर। राजधानी रायपुर में भारी विवादों के बीच जीई रोड के किनारे साइंस कॉलेज मैदान के करीब 6 करोड़ की लागत से बनाए गए चौपाटी को हटाने की तैयारी है. विधायक राजेश मूणत ने रायपुर स्मार्ट सिटी परामर्शदात्री समिति की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए हैं. अब यहां पर छात्रों के लिए ओपन रीडिंग और बच्चों के प्ले जोन का निर्माण किया जाएगा.

वित्त मंत्री चौधरी औचक निरीक्षण में पहुंचे पुसौर स्कूल

रायगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जिले रायगढ़ प्रवास के दौरान विकास खंड पुसौर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के औचक निरीक्षण में पहुंचे। मंत्री श्री चौधरी ने स्कूल का भ्रमण कर विद्यालय के मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। यहां उन्होंने विद्यालय में प्रयोगशाला निर्माण के लिए 20 लाख रूपये तथा पुस्तकालय के पुस्तकों हेतु 02 लाख रुपये की घोषणा किया।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 04 से 05 वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य बना कर कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ाई करें,ताकि आपका भविष्य बन सके। उन्होंने कहा कि आज के दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है,शुरूआती असफलताओं से निराश और हताश न हो कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करें। बड़ी सोच और रणनीति बना कर पढ़ाई करें,तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि आज भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। यहां अलग - अलग क्षेत्र में कैरियर के विभिन्न अवसर तैयार हो रहे है। आपको उस अवसर को प्राप्त करने के लिए तैयार होना होगा। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों पर चर्चा कर करते हुए टिप्स के साथ ही कैरियर के विभिन्न विकल्प की जानकारी भी दी।

स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन

स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य, समाज व पर्यावरण के लिए आवश्यक- कलेक्टर

जांजगीर-चांपा । जिला प्रशासन द्वारा 17 सितंबर से चलाये स्वच्छता पखवाड़े के समापन व राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया गया । विदित हो कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अन्तर्गत यह अभियान जिले में चलाया इस अवसर पर कलेक्टर आकाश छिकारा ने अपने सम्बोधन में कहा कि स्वच्छता न केवल हमारे परिवेश को साफ और सुंदर बनाए रखने का उद्देश्य है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, समाज और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है।जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम में स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छ भारत दिवस सम्मान समारोह में कलेक्टर आकाश छिकारा ने आगे कहा कि स्वच्छता न केवल शासन, नगरपालिका या सफाईकर्मियों का कार्य नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने घर, गली, मोहल्ले, और शहर को स्वच्छ बनाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हम सब को स्वास्थ्य के प्रति एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने

आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कार्यक्रम में आये महिलाओं को अपने परिवार के सभी सदस्यों का पंजीयन कराने कहा। इसके साथ ही कलेक्टर ने जिले में संचालित नवाचार कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह और गुलाब सिंह चंदेल ने कार्यक्रम को संबोधित किया।इस दौरान नवागढ़ जनपद के अध्यक्ष श्रीमती प्रीति देवी सिंह, अपर कलेक्टर एसपी वैद्य, ज़िला पंचायत सभापति गगन जयपुरिया, सीईओ जिला पंचायत गोकुल रावटे, बड़ी संख्या में स्व सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालय शा. प्राथमिक शाला सोनडीह, अमलीपाली, शा. प्राथमिक शाला सिल्ली, शा. प्राथमिक शाला नवापारा-ब, शा. प्राथमिक शाला पीथमपुर, शा. प्राथमिक शाला लखुर्री को सम्मानित किया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- गुलाब दास दीवान, द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित। RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक- गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139